घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 18- मंगलवार 18- नवम्बर 2025,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये ,www.ghatati-ghatana.com,RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2023-2025

मक्का से मदीना जा रहे 45 भारतीयों की मौत...

उमरा के लिए जा रही बस डीजल टैंकर से टकराकर जली,सिर्फ ड्राइवर जिंदा बचा

नई दिल्ली,17 नवम्बर 2025। सऊदी अरब में सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई। मक्का से मदीना जाते समय इनकी बस डीजल टैंकर से टकरा गई और इसमें आग लग गई। मृतकों में 18 महिलाएं,17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर ही जिंदा बचा। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक, 9 नवंबर को 54 लोग हैदराबाद से सऊदी गए थे। वे 23 नवंबर को वापस आने वाले थे। इनमें से 4 लोग रविवार को कार से अलग से मदीना गए थे। वहीं 4 लोग मक्का में रुक गए थे। दुर्घटना वाली बस में 46 लोग सवार थे।

मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। हादसा मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर मुहरास के पास भारतीय समयानुसार रात लगभग 1:30 बजे हुआ। उस समय कई यात्री सो रहे थे। उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि वह रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे दूतावास से नजदीकी तालमेल बनाकर पीड़ितों की पहचान और अन्य औपचारिकताओं में मदद करें। हादसे में मारे गए लोगों में से 12 भारतीय पीड़ितों की पहचान हो पाई है, उनमें अब्दुल मोहम्मद, मोहम्मद मौलाना, सोहेल मोहम्मद, मस्तान मोहम्मद, परवीन बेगम, जकिया बेगम, शौकत बेगम, फरहीन बेगम, जहीन बेगम, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद अली, गौसिया बेगम शामिल हैं। जेद्दा में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन जारी किया है। दूतावास ने कहा , 'सऊदी अरब के मदीना के निकट भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों के साथ हुई दुखद बस दुर्घटना को देखते हुए , जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 24×7 कंट्रोल रूम बनाया हेल्पलाइन का संपर्क विवरण 8002440003 है।

घटना के बाद तेलंगाना सरकार ने सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया है, ताकि परिजन अपने परिजनों के बारे में जानकारी ले सकें। परिवारजन इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: 79979-59754 और 99129-19545 ।

ओवैसी ने शवों को भारत लाने की अपील की...

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में भारतीय उमरा यात्रियों की बस दुर्घटना पर दुख जताया है। ओवैसी ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद की दो ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों की जानकारी रियाद स्थित भारतीय दूतावास के साथ साझा की है। उन्होंने रियाद में भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू मैथन जॉर्ज से भी बात की। जॉर्ज ने उन्हें बताया कि स्थानीय अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही अपडेट दिया जाएगा। ओवैसी ने कहा- मैं केंद्र सरकार से, खासकर विदेश मंत्री जयशंकर से अपील करता हूं कि शवों को जल्द ले जल्द भारत लाया जाए और घायलों को जरूरी चिकित्सा मुहैया कराई जाए।

पीएम मोदी बोले...पीड़ितों को हरसंभव मदद दे रहे...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सऊदी बस दुर्घटना पर दुख जताया। एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि रियाद में वाणिज्य दूतावास हर संभव मदद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा, 'मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं।'

विदेश मंत्री बोले... दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब में हुए हादसे पर दुख जताया। जयशंकर ने कहा- 'मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं।'

नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक में तीन प्रस्तावों पर मुहर,मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा

पटना,17 नवम्बर 2025 । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक में तीन प्रस्तावों पर मुहर लगने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा प्रदेश के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दिया। उनके इस्तीफे के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उनसे नई सरकार के गठन होने तक राज्य का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का आग्रह किया है। इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार ने सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक की। बैठक में मंत्रीमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पास हुआ। इससे पहले नीतीश कुमार की आज संपन्न

आखिरी कैबिनेट बैठक में कुल तीन प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल तीन प्रस्ताव पास हुए। पहले प्रस्ताव के तहत, मंत्रिमंडल ने 19 नवंबर से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की है। दूसरे प्रस्ताव में पूरे कार्यकाल के दौरान बिहार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिए गए सकारात्मक सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया। तीसरे प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को मिले भारी बहुमत के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी और आभार व्यक्त किया। सूत्रों के मुताबिक 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। उनके साथ-साथ 31 मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं।

शेख हसीना को मिली फांसी की सजा...

बांग्लादेश कोर्ट ने छात्रों की हत्याओं का दोषी माना,हसीना बोलीं...फैसला राजनीति से प्रेरित

ढाका,17 नवम्बर 2025। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 5 में से दो मामले, हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश के लिए मौत की सजा दी। जबकि बाकी मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई। ट्रिब्यूनल ने उन्हें जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा। ट्रिब्यूनल ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। वहीं, तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल-ममून को 5 साल के जेल की सजा सुनाई। ममून हिरासत में हैं और सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। शेख हसीना के अलावा पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमान ने 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट के बाद देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं।

हसीना ने जिस कोर्ट की स्थापना की, उसी ने सजा सुनाई : हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने ही की थी। इसे 2010 में बनाया गया था। इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वॉर क्राइम्स और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सजा के लिए बनाया गया था। हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में ही कानून बना दिया गया था, लेकिन दशकों तक प्रक्रिया रुकी रही। इसके बाद 2010 में हसीना ने इसकी स्थापना की ताकि अपराधियों पर मुकदमा चल सके।

हसीना बोलीं...ये फैसला गलत और पक्षपाती...

शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत,पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर-निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि यह पूरा मामला असली घटनाओं की जांच नहीं, बल्कि अवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है। हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार में पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है। न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई है,अवामी लीग समर्थकों और हिंदू-मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता जा रहा है। हसीना ने कहा कि डॉ. यूनुस को किसी ने चुना नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का अगला चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए।

हसीना फैसले खिलाफ 30 दिन में याचिका दायर कर सकती हैं...

इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमान को 30 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार दिया गया है। यह अपील बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपील डिवीजन में दाखिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट को 60 दिनों के भीतर इस अपील पर फैसला देना अनिवार्य है। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है कि अपील 'इन एब्सेंटिया' यानी देश से बाहर रहकर नहीं की जा सकती। अपील करने के लिए दोषियों का शारीरिक रूप से बांग्लादेश में मौजूद होना जरूरी है।

अटॉर्नी जनरल बोले...हसीना के गिरफ्तार होते ही फैसला अमल में लाएंगे...

बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल असदुज्जमान ने कहा है कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाई गई सजा गिरफ्तारी के उसी दिन से लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि यह सजा आगे के लिए टाली नहीं जाएगी,बल्कि गिरफ्तारी होते ही तुरंत अमल में लाई जाएगी। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में दो आरोपियों को मौत की सजा दी गई है।

दिल्ली ब्लास्ट : आतंकी उमर का श्रीनगर से एक साथी गिरफ्तार

नई दिल्ली,17 नवम्बर 2025। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से आतंकी उमर के एक और साथी जसीर बिलाल वाणी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया। आरोप है कि जसीर आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देता था। विस्फोट के लिए ड्रोन मॉडिफाई करता था और रॉकेट बनाने की भी कोशिश की थी। एनआईए के मुताबिक जसीर आतंकी उमर का प्रमुख सहयोगी है। वह अनंतनाग के

काजीकुंड का रहने वाला है। दिल्ली ब्लास्ट में इसकी सक्रिय भूमिका रही है। डॉ. उमर के साथ मिलकर ब्लास्ट की प्लानिंग में शामिल था। वहीं दिल्ली से गिरफ्तार आमिर राशिद अली को लेकर खुलासा हुआ है कि ब्लास्ट से पहले उसने उमर को सेफ हाउस (सुरक्षित ठिकाने) उपलब्ध कराए, आईईडी बनाने में भी मदद की थी। ये दलील सोमवार को एनआईए ने स्पेशल एनआईए कोर्ट में आमिर की कस्टडी पाने के लिए दीं।

अनिल अंबानी ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को फिर किया नजरअंदाज,मुख्यालय में नहीं हुए पेश

नई दिल्ली,17 नवम्बर 2025। रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी जयपुर-रींगस हाइवे प्रोजेक्ट से जुड़ी फेमा जांच में सोमवार को दूसरे समन के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। हालांकि,उन्होंने वर्चुअल पेशी का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से अनिल अंबानी को दिल्ली के ईडी मुख्यालय में पेश होना था,लेकिन वे पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे और वर्चुअल पेश की अनुमति मांग थी, जिस पर जांच एसेंजी ने

इनकार करते हुए, सोमवार को पेशी के लिए दूसरा समन जारी किया था। ईडी सूत्रों के अनुसार, एजेंसी फेमा के तहत उनका बयान दर्ज करना चाहती है। यह जांच उन आरोपों के बाद शुरू हुई थी, जिसमें कहा गया था कि रिलायंस इंफ्रा ने 2010 में मिले हाइवे प्रोजेक्ट के लगभग 40 करोड़ रुपए को सूरत स्थित फर्जी कंपनियों के माध्यम से दुबई भेज दिया था। जांचकर्ताओं का यह भी मानना है कि पैसों का यह लेन-देन एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क से जुड़ा है, जिसका अनुमानित आकार 600 करोड़ रुपए से अधिक है। अनिल अंबानी ने पहले जारी समन के जवाब में शुक्रवार को ईडी के समक्ष वर्चुअल पेशी के लिए ईमेल के जरिए अनुरोध भेजा था। हालांकि, वित्तीय जांच एजेंसी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उन्हें 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए एक और समन जारी करने का फैसला किया। रिलायंस समूह के एक प्रवक्ता ने एक ताजा बयान में कहा कि 'अनिल अंबानी ने ईडी के लिए उपयुक्त किसी भी तारीख और समय पर वर्चुअल उपस्थिति/रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से अपना बयान दर्ज कराने के लिए खुद को उपलब्ध कराने की पेशकश की है।' प्रवक्ता ने आगे कहा, 'अनिल डी. अंबानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड के सदस्य नहीं हैं।

बेतिया में कार ने बारातियों को रौंदा

3 की मौत,15 से ज्यादा घायल

पटना,17 नवम्बर 2025 । बेतिया में बेकाबू कार ने बारातियों को रौंद दिया, जिसमें 3 की मौत हो गई, जबकि 16 जख्मी हैं। हादसा बेतिया-बगहा नेशनल हाईवे पर बिशुनरवा गांव के पास हुआ। मरने वालों में दूल्हे के फूफा और अगुआ भी हैं। जबकि घायलों में से 2 की हालत नाजुक है। एक्सीडेंट दुल्हन के घर के सामने हुआ। सभी बाराती खाना खाकर सड़क पार कर रहे थे, तभी बेकाबू कार ने कुचल दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को लौरिया सीएचसी में भर्ती कराया। अस्पताल पहुंचे बारातियों के परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा कर जमकर हंगामा किया। लोगों का आक्रोश देखकर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ इधर-उधर छिपने लगे। कुछ लोगों से मारपीट भी हुई। जिसके कारण अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी रही। लोगों के आक्रोश के सामने पुलिस बेबस दिखी।

सपा नेता आजम और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा

नई दिल्ली,17 नवम्बर 2025। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर 7-7 साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सोमवार को दोनों को दोषी करार दिया। फैसले के तुरंत बाद कोर्ट में ही पुलिस ने बाप-बेटे को हिरासत में ले लिया। दोनों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट से एक किमी दूर गाड़ी से रामपुर जेल लेकर गई। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। आजम पुलिस की बोलेरो से जेल के बाहर उतरे तो एक हाथ में चश्मे का केस, दो पैकेट बिस्किट थे। फिर अब्दुल्ला गाड़ी से उतरा, उसके हाथ खाली थे। आजम के साथ उनका बड़ा बेटा अदीब भी पीछे-पीछे गाड़ी से जेल के गेट तक पहुंचा। उसने पिता आजम के कान में कुछ कहा, लेकिन क्या कहा, यह क्लियर नहीं है। जेल में दाखिल होने से पहले आजम ने कहा- कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है। वहीं, आजम के जेल जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा- सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं। वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब, सब देख रहे हैं।

कार से 5 करोड़ रुपए जब्त किए,दो गिरफ्तार,इतना कैश कि फटी रह गई आंखें

कोलकाता,17 नवम्बर 2025। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पांच करोड़ रुपए की नकदी के साथ कार सवार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह पैसा न्यू टाउन इलाके से लाया जा रहा था। आकांक्षा क्रॉसिंग के पास कार को पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल एसटीएफ को नकदी ले जा रहे कार सवार लोगों के बारे में सूचना मिली थी। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने न्यू टाउन में आकांक्षा क्रॉसिंग के पास लक्षित वाहनों की जांच शुरू की। अभियान के दौरान, टीम ने एक कार को रोका और उसमें सवार दो लोगों से पूछताछ की। कार की गहन तलाशी में नकदी से भरे बैग मिले। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'तलाशी के बाद कार से पांच करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। नकदी को जब्त किया गया है और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।'

राजस्थान के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में शुरू हुआ भारत-यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास 'अजेय वॉरियर'

बीकानेर,17 नवम्बर 2025। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 'अजेय वॉरियर-25' का आठवां संस्करण सोमवार को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आरंभ हुआ। यह द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय अभ्यास 30 नवंबर तक चलेगा। अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के कुल 240 सैनिक शामिल हैं,जिनमें समान प्रतिनिधित्व रखा गया है। भारत की ओर से सिख रेजीमेंट के जवान भाग ले रहे हैं, जबकि ब्रिटेन की ओर से 1एसटी डिवीजन की 4th लाइट ब्रिगेड के 2nd बटालियन, रॉयल गोरखा राइफल्स के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। कर्नल नीरज बेनीवाल ने कहा कि यह संयुक्त प्रशिक्षण संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है

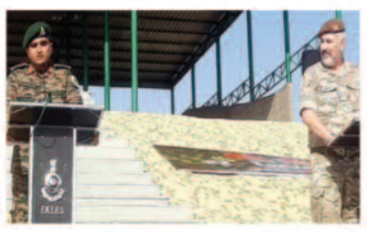

और इसका मुख्य फोकस शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद-रोधी अभियानों पर है। आगामी 14 दिनों में सैनिक संयुक्त मिशन योजना, ब्रिगेड-स्तरीय सामरिक समन्वय, सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण और कंपनी-स्तरीय वास्तविक फील्ड अभ्यास करेंगे।

सेना प्रमुख की पाकिस्तान को चेतावनी..पड़ोसी से 'कैसे व्यवहार करना है'सिखाने के लिए भारत तैयार

नई दिल्ली,17 नवम्बर 2025 । सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को चाणक्य डिफेंस डायलॉग में फिर एक बार ऑपरेशन 'सिंदूर' के बारे में कहा कि फिल्म तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, ये तो बस 88 घंटे का ट्रेलर था। हम भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान हमें मौका दे,तो हम उन्हें सिखाएंगे कि एक पड़ोसी को कैसा व्यवहार करना चाहिए। जनरल द्विवेदी ने कहा कि हम आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। हम उन लोगों को जवाब देंगे, जो आतंकवादियों को प्रोत्साहित करते हैं। जनरल द्विवेदी ने यहां मानेकशा सेंटर में आज चाणक्य डिफेंस डायलॉग में उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति सेना के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। ऑपरेशन सिंदूर पर थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि जब कोई देश राज्य प्रायोजित आतंकवाद को

बढ़ावा देता है,तो यह भारत के लिए चिंता का विषय बन जाता है। भारत प्रगति की बात करता है। अगर कोई हमारे रास्ते में बाधा डालता है, तो हमें उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी होगी। हमने कहा है कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि हम केवल एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के लिए कह रहे हैं,जिसमें हम सहयोग करेंगे। तब तक हम आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। हम उन लोगों को जवाब देंगे, जो आतंकवादियों को प्रोत्साहित करते हैं। आज,भारत इतना कुशल है कि वह किसी भी ब्लैकमेल के प्रयासों से नहीं डरता। उन्होंने कहा कि आज के समय में लड़ाई कई क्षेत्रों में होती है। हम नहीं कह सकते कि यह कब तक चलेगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास लंबे समय तक चलने वाली रसद उपलब्ध रहे। हमारे पास राजनीतिक इच्छाशक्ति है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। आज के समय में हमारी प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसके बाद राजनीतिक स्पष्टता आई है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में भारी कमी आई है।

संपादकीय

आतंकवाद नहीं,जिहादी हिंसा...

राजनीतिक-बौद्धिक वर्ग को तथ्य-आधारित समझ की आवश्यकता

क ई दशकों से जिहादी हिंसा पर इस कहावत के उलट काम किया जा रहा है कि जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। जो काम सुई का है,वैचारिक-शैक्षिक संघर्ष का है, उसे तलवार, सैन्य-प्रहार आदि से हराने की कोशिश हो रही है। लोकतांत्रिक विश्व आत्म-प्रवंचना में है। लिहाजा आतंक बरपाने वाले नए-नए दस्ते, संगठन, सरगना इसलिए आते रहते हैं,क्योंकि उन्हें मौत का, तलवार का भय ही नहीं है। केवल तलवार उन पर निष्फल भी रहती है। जिसे आतंकवाद कहा जाता है, उसे आतंकी खुद जिहाद कहते हैं और अपने को मुजाहिदीन। भारत में एक संगठन का नाम ही इंडियन मुजाहिदीन था। इसने लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली, मुंबई आदि शहरों पर अनेक बम-विस्फोट किए, जिनमें सैकड़ों नागरिक मारे गए। जिहाद की संज्ञा भारत में सैकड़ों वर्षों से बार-बार गूंजती रही है। गजनवी से लेकर बाबर जैसे बड़े-बड़े हमलावरों,सुल्तानों,बादशाहों तथा मौदूदी,इकबाल जैसे बड़े-बड़े आलिमों के मुंह और कलम से। फिर भी हमारा राजनीतिक-बौद्धिक वर्ग जिहाद पर चुप रहता है। वह उससे मुकाबला कैसे कर सकता है, जिससे आंख मिलाकर देखने में भी उसे संकोच है?

यदि मुजाहिदीनों द्वारा की गई हिंसा और आतंक का मुकाबला करना है तो वास्तव में जिहाद का सामना करना होगा। उसे उग्रवाद,आतंकवाद, विकृति आदि नाम देना झूठे उपायों की ओर ले जाता है। इसे अफगानिस्तान-पाकिस्तान में अमेरिकी विफलता में बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। एक संगठन के बाद, दूसरे पैदा हो जाते हैं। एक सरगना के बाद दूसरा आ जाता है। एक भारतीय इमाम ने कहा था, एक ओसामा मरेगा, तो सौ पैदा होंगे। जिस विश्वास से उन्होंने ऐसा कहा था,उस पर विचार और चोट करनी चाहिए तब समाधान मिलेगा। जिहाद से अनजान लोग ही जिहादियों का सबसे बड़ा कवच हैं।

जिहाद का सिद्धांत मानवता को दो हिस्से में बांटकर देखता है-इस्लाम मानने वाले और नहीं मानने वाले। इसी से इस सिद्धांत की दोहरी नैतिकता बनती है। मुस्लिम के साथ एक व्यवहार और काफिरों के साथ दूसरा। इसी से 'दारुल-इस्लाम' (जहां मुसलमानों का शासन हो) और 'दारुल-हरब' (जहां काफिरों का शासन हो) की धारणा है। इसी कारण यहूदियों से कहा गया था कि सारी दुनिया केवल मुसलमानों के लिए है और वे जान बचाने को इस्लाम कबूल करें। यही दावा राजनीतिक इस्लाम है और इसे लागू करने की गतिविधि जिहाद है।

इतिहास को झुठलाने की मांग करने से लेकर सब पर शरीयत लादने, हलाल थोपने तक उसके असंख्य शांतिपूर्ण रूप हैं।

नीतीश की नई सरकार में जेडीयू-बीजेपी की बराबरी साझेदारी

"बिहार की राजनीति में यह वह क्षण है, जब सत्ता के गलियारे नए समीकरणों से भरे हुए हैं और गठबंधन की राजनीति अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत ने महागठबंधन को भारी झटका दिया है, लेकिन उससे भी बड़ा संदेश यह है कि इस बार जो राजनीतिक परिदृश्य बना है, वह पिछले दो दशकों की तुलना में एकदम अलग और बिल्कुल नई बुनियाद पर टिकने वाला मॉडल तैयार कर रहा है...

अजय कुमार,
लखनऊ,उत्तरप्रदेश.

पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को होने वाला शपथ ग्रहण सिर्फ सरकार गठन का औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि यह उस नए सत्ता-संतुलन की शुरुआत होगी, जिसमें जेडीयू और बीजेपी को पहली बार वास्तविक बराबरी वाली स्थिति में देखा जा रहा है। इस बार की चुनावी जंग में एनडीए ने सीट बंटवारे का जो फार्मूला अपनाया था, उसने राजनीति के पुराने मापदंडों को बदल दिया। जेडीयू और बीजेपी दोनों ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा और नतीजों ने इस बराबरी के प्रयोग को सियासी तौर पर मजबूती प्रदान की है। दोनों दलों के बीच केवल चार सीटों का अंतर होना इस बात का संकेत है कि सियासत का पलड़ा अब किसी एक तरफ़ भारी नहीं है। यही वजह है कि इस बार की सरकार में मंत्रिमंडल का हिस्सा भी उसी बराबरी वाले फार्मूले पर टिक सकता है।

यह स्थिति 2020 से बिल्कुल उलट है। 2020 में बीजेपी की 74 सीटें थीं और जेडीयू की महज 43, जिसके कारण 12-22 वाला मंत्रिमंडलीय बंटवारा बना था। तब बीजेपी का राजनीतिक कद जेडीयू से ज्यादा दिख रहा था,लेकिन इस बार नतीजों ने गठबंधन के भीतर की शक्ति-संरचना को पूरी तरह संतुलित कर दिया है। 2025 में एनडीए के कुल 202 विधायक हैं जिसमें बीजेपी के 89, जेडीयू के 85, एलजेपी (रामविलास) के 19,हम के 5,और आरएलएम के 4 विधायक शामिल हैं। इन आँकड़ों की रोशनी में यह स्पष्ट है कि नये मंत्रिमंडल के गठन में पुराने फार्मूले का दोहराया जाना लगभग असंभव है।राजनीतिक समीकरणों की गणना से यह बात भी सामने आ रही है कि गठबंधन इस बार 6 विधायक पर 1 मंत्री का फार्मूला अपना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू और बीजेपी दोनों ही लगभग 15-16 मंत्री दे सकेंगे। साथ ही छोटे दलों चिराग पासवान की पार्टी, मांझी की हम और कुशवाहा की आरएलएम को भी उचित प्रतिनिधित्व देने के संकेत हैं। चिराग की पार्टी को 2-3 मंत्री, जबकि मांझी और कुशवाहा को 1-1 मंत्री मिलना संभावित माना जा रहा है। यह संयोजन दिखाता है कि एनडीए इस बार सिर्फ बड़ा दिखने की राजनीति नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की संतुलित भूमिका अपनाना चाहता है। डिप्टी सीएम का समीकरण भी इस बार बेहद दिलचस्प होगा। 2005 से लेकर 2024 तक बीस सालों में एक परंपरा बनी रही कि जब-जब जेडीयू और बीजेपी साथ हुए, बीजेपी के हिस्से में डिप्टी सीएम की कुर्सी गई। सुशील मोदी हों, तारकेश्वर प्रसाद या रेणु देवी हर दौर में यह कुर्सी बीजेपी ने ही संभाली। 2024 की शुरुआत में जब नीतीश दोबारा एनडीए में आए तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। अब सवाल यह है कि नए मंत्रिमंडल में बीजेपी को एक डिप्टी सीएम मिलेगा या दो? और क्या जेडीयू इस बार डिप्टी मुख्यमंत्री पद पर दावा पेश कर सकता है? हालाँकि संकेत यही हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन की एकता बनाए रखने के लिए वही पुराना पैटर्न बरकरार रखेंगे और बीजेपी को ही डिप्टी सीएम का दायित्व मिलेगा, पर अंदरखाने मंथन लगातार जारी है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा संतुलन, समझौता और स्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने के कौशल पर आधारित रही है। इस बार भी वे उसी रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू को बराबरी की हिस्सेदारी दिलवाकर वे न केवल जाति-आधारित समीकरणों को मजबूती दे रहे हैं, बल्कि यह संदेश भी भेज रहे हैं कि जेडीयू अब किसी भी स्थिति में जूनियर पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं। उनकी रणनीति यह दिखाती है कि वे 2020 की तरह का परिदृश्य नहीं दोहराना चाहते, जिसमें बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया था और जेडीयू कमजोर स्थिति में चली गई थी।

बिहार का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा से संख्या, जाति और गठबंधन की बारीकियों पर टिका रहा है। इस बार के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में सत्ता की लड़ाई अब सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि गठबंधन के भीतर भी शक्ति का संतुलन उतना ही अहम होगा। एनडीए की नई सरकार अगर 50-50 वाले मॉडल पर खड़ी होती है, तो यह बिहार में राजनीतिक साझेदारी के एक नए अध्याय का संकेत होगा। यह वह मॉडल होगा जिसमें दोनों बड़े दलों को बराबर का सम्मान, बराबर का स्थान और बराबर का दायित्व मिलेगा। हालाँकि चुनौतियाँ कम नहीं हैं। बराबरी की साझेदारी का अर्थ यह भी है कि किसी भी मुद्दे पर मतभेद उत्पन्न होने पर गठबंधन में तनाव बढ़ सकता है। दोनों दलों को मंत्रियों के चयन में समाजिक संतुलन भी ध्यान में रखना होगा अगड़े,पिछड़े,महादलित, अल्पसंख्यक,अत्यंत पिछड़ा वर्ग इन सभी का उचित प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल की अनिवार्य शर्त है। छोटे दलों की अपेक्षाएँ भी गठबंधन के लिए परीक्षा बन सकती हैं,क्योंकि शक्ति-साझेदारी में थोड़ी भी कमी उन्हें गठबंधन से दूर कर सकती है।

इसके बावजूद यह भी सच है कि इस बार एनडीए के पास बिहार को राजनीतिक स्थिरता देने का बड़ा अवसर है। यदि यह सरकार संयुक्त जिम्मेदारी और साझा नेतृत्व के सिद्धांत पर चलती है, तो यह बिहार के विकास मॉडल को भी नई दिशा दे सकती है। बेरोजगारी,पलायन,उद्योगों का अभाव,शिक्षा और स्वास्थ्य इन सभी मोर्चों पर काम करने के लिए स्थायी और संतुलित सरकार की ज़रूरत है। और यह सरकार वैसी बनने की क्षमता रखती है, बशर्ते गठबंधन के भीतर संवाद और तालमेल कायम रहे।नीतीश कुमार की नई पारी ऐसे समय में शुरू हो रही है जब बिहार की जनता राजनीतिक उथल-पुथल से थक चुकी है। लोग स्थिरता चाहते हैं, नीतिगत निरंतरता चाहते हैं और विकास की गति चाहते हैं। यदि जेडीयू और बीजेपी अपनी बराबरी वाली साझेदारी को सियासी अहंकार से दूर रखते हुए चलाएँ, तो यह सरकार आने वाले वर्षों में बिहार की दिशा बदलने का अवसर बन सकती है।

यूपी में जातीय रैलियों पर रोक से संगठित होता हिन्दुत्व

देश में क्या विभाजनकारी राजनीति करने वाले नेताओं का अंत का समय करीब आ गया है। बिहार के नतीजों ने क्या बांटने और राज करने की राजनीति करने वाले नेताओं को सबक सिखा दिया है कि उन्हें अपनी भविष्य की राजनीति में बदलाव करना होगा...

बिहार से जो संदेश निकला है,उसका प्रभाव अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश इससे सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। वैसे भी यूपी की योगी सरकार ने हाल ही में जातीय आधार पर होने वाली रैलियों पर प्रतिबंध लगाकर राजनीतिक दृश्य में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। इस फैसले का भी सीधा असर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों पर पड़ा है, जो लंबे समय से जाति आधारित राजनीति को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाए हुए हैं।योगी सरकार का यह कदम न सिर्फ राज्य की राजनीतिक संस्कृति को बदलने की कोशिश है,बल्कि यह बीजेपी के लिए एक रणनीतिक फायदा भी बन सकता है। जातीय रैलियों पर रोक लगाकर योगी सरकार उन नेताओं और दलों के मंसूबे चकनाचूर करना चाहती है, जो हिंदू समाज को जाति और उपजाति के आधार पर बांटने की सियासत में लगे रहते हैं। इस फैसले के पीछे यह विश्वास है कि जातीय रैलियां समाज में विभाजन और तनाव पैदा करती हैं,जिससे राज्य की शांति और सद्भावना को खतरा होता है।

संजय सक्सेना,
लखनऊ,उत्तरप्रदेश.

योगी सरकार का तर्क है कि राजनीति को जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और समानता के आधार पर होना चाहिए। इस निर्णय से अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेताओं के लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि उनकी राजनीतिक रणनीति जाति आधारित वोट बैंक को जोड़ने पर टिकी हुई है। अब उन्हें नए तरीके से जनता को संबोधित करना होगा, जिसमें जाति की बजाय विकास और समानता के मुद्दे आगे आएंगे।यह फैसला बीजेपी के लिए एक बड़ा रणनीतिक फायदा भी है। बीजेपी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में हिंदू एकता की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। जातीय रैलियों पर प्रतिबंध लगाकर योगी सरकार ने बीजेपी की इस रणनीति को और मजबूत किया है। अब जाति आधारित रैलियों के बिना अखिलेश यादव और मायावती के लिए अपने वोट बैंक को जोड़ना मुश्किल होगा, जबकि बीजेपी के लिए यह एक अवसर है कि वह हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट कर सके। इससे 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट बैंक का विस्तार हो सकता है।

गौरतलब है, बिहार के चुनावों में भी इसी तरह की राजनीतिक दिशा देखने को मिली है। बिहार में हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों ने एकजुट होकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में मतदान किया। इस एकजुटता का असर यह हुआ कि जाति आधारित राजनीति करने वाले दलों को बड़ा झटका लगा। बिहार के चुनाव ने यह संकेत दिया कि अब हिंदू समाज जाति और उपजाति के आधार पर नहीं, बल्कि विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर वोट देने लगा है। यह रुझान उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, खासकर जब जातीय रैलियों पर प्रतिबंध लग चुका है।योगी सरकार का यह कदम न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा संदेश है। यह संदेश है कि अब जाति और उपजाति के आधार पर विभाजन की राजनीति नहीं चलेगी। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार चाहती है कि राजनीति विकास, सुरक्षा और समानता के मुद्दों पर आधारित हो। इससे न सिर्फ राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी होगी, बल्कि जनता को भी अपने वोट के आधार को बदलना होगा।

इस फैसले के बाद अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेताओं के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे अपने वोट बैंक को जाति के आधार पर नहीं, बल्कि विकास और समानता के मुद्दों पर जोड़ें। इससे उन्हें नए तरीके से जनता को संबोधित करना होगा, जिसमें जाति की बजाय विकास और समानता के मुद्दे आगे आएंगे। इस तरह की रणनीति अपनाने से उन्हें बीजेपी के खिलाफ एक नई राजनीतिक दिशा देनी होगी।योगी सरकार का यह कदम बीजेपी के लिए एक बड़ा रणनीतिक फायदा भी है। बीजेपी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में हिंदू एकता की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। जातीय रैलियों पर प्रतिबंध लगाकर योगी सरकार ने बीजेपी की इस रणनीति को और मजबूत किया है। अब जाति आधारित रैलियों के बिना अखिलेश यादव और मायावती के लिए अपने वोट बैंक को जोड़ना मुश्किल होगा, जबकि बीजेपी के लिए यह एक अवसर है कि वह हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट कर सके। इससे 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट बैंक का विस्तार हो सकता है। बिहार के चुनावों में भी इसी तरह की राजनीतिक दिशा देखने को मिली है। बिहार में हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों ने एकजुट होकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में मतदान किया। इस एकजुटता का असर यह हुआ कि जाति आधारित राजनीति करने वाले दलों को बड़ा झटका लगा। बिहार के चुनाव ने यह संकेत दिया कि अब हिंदू समाज जाति और उपजाति के आधार पर नहीं, बल्कि विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर वोट देने लगा है। यह रुझान उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, खासकर जब जातीय रैलियों पर प्रतिबंध लग चुका है।योगी सरकार का यह कदम न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक बड़ा संदेश है। यह संदेश है कि अब जाति और उपजाति के आधार पर विभाजन की राजनीति नहीं चलेगी। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार चाहती है कि राजनीति विकास, सुरक्षा और समानता के मुद्दों पर आधारित हो। इससे न सिर्फ राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी होगी, बल्कि जनता को भी अपने वोट के आधार को बदलना होगा।

चुनाव सुधार:भ्रामक प्रचार का समाधान आवश्यक

महाराष्ट, हरियाणा और बिहार में जनमानस ने जिस प्रकार से खुलकर मतदान किया,उससे स्पष्ट हो गया है, कि जनता आधी छो पूरी को ध्यावे पूरी मिले न आधी पावे, जैसे सत्य को समझ चुकी है। वह सत्ता प्राप्ति के लिए किये जाने वाले अकल्पनीय सुविधाओं के वादों पर यकीन नहीं करती। वह अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अराजकता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। वह अतीत का स्मरण करके सोच समझकर निर्णय लेती है, भावनाओं में बहकर मतदान नहीं करती।

डॉ. सुधाकर आशावादी
विनायक फीचर्स

इतिहास साक्षी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे प्रदेश रहे हैं, जिनमें एक समय में अराजकता अपनी चरम सीमा पर रही। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से आम आदमी का जीना मुहाल था, से कों पर चलना भी सुरक्षित नहीं था, उस स्थिति से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने प्रदेश की सत्ता से समाजवादी पार्टी को बेदखल किया। उसी प्रकार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के शासन काल में जंगलराज से निजात पाने के लिए जनता ने नीतीश कुमार को अपना मत एवं समर्थन दिया,जो लम्बे समय से बरे रार है।

मतदाताओं ने जाति व धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर सुशासन को ही एकमात्र विकल्प मानकर बे चे कर मतदान किया तथा चुनाव को प्रभावित करने के लिए नाकारा व अस्तित्वहीन राजनीतिक दलों के झूठे व भ्रामक विमर्श को नकार दिया तथा स्पष्ट सन्देश दिया कि स्वस्थ लोकतंत्र में आम मतदाता किसी भी वंशवादी राजनीतिक दल या नकारात्मक राजनीति करने वाले अराजक तत्वों का गुलाम नहीं है।

कहना गलत न होगा, कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए देश,काल और परिस्थिति के अनुसार समय समय पर चुनाव सुधार किये जाने आवश्यक हैं। देश का दुर्भाग्य है,कि अपनी संकीर्ण राजनीति के चलते कतिपय राजनीतिक दल चुनाव सुधारों का विरोध करते रहे हैं। बिहार हो अथवा बंगाल,इन राज्यों में एस.आई.आर. का विरोध केवल इसलिए किया गया,कि लाखों की संख्या में बने फर्जी वोटों को न काटा जाए। अब जब पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा पश्चिमी बंगाल में अवैध रूप से बसे घुसपैठियों को खदे ा जा रहा है, तब राजनीतिक दलों में अधिक बौखलाहट दिखाई दे रही है।

बिहार चुनाव परिणामों ने जाति आधारित राजनीति करने वाले विघटनकारी तत्वों की नींद उड़ा दी है। उन्हें एक समय में दिल्ली में हुए चुनावों में आम आदमी पार्टी की बम्पर विजय पर कोई संदेह नहीं हुआ,अब बिहार में आम आदमी द्वारा सुशासन के पक्ष में बे चे कर दिया गया जनादेश उन्हें हजम नहीं हो पा रहा है।

समझ नहीं आता,कि एक ही प्रकार के जनादेश को वे प्रतिकूल नजरिए से देखने की निर्लज्जता कैसे दिखा सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने, फर्जी वोट काटने की प्रक्रिया को सतर्कता से पूर्ण किया जाना चाहिए,ताकि चुनावों की निष्पक्षता पर किसी भी प्रकार से भ्रामक विमर्श को विस्तार का अवसर न मिले। *

कविता

जीवन को कृतार्थ हैं बनाना

मोनिका डागा
आनंद ,
चेन्नई,तमिलनाडु

परिस्थिति चाहे हो या नहीं हो अपने बस में,
मन की स्थिति को हमें एकाग्र व शांत है रखना,
कुछ लोग आशीर्वाद व दुआएं देंगे जीवन में,
कुछ चोट भी पहुंचाएंगे हमें आभार है जताना ।

होता हैं नित नया कुछ न कुछ घटित प्रकृति में,
चिड़िया चिंता छोड़ फिर भी गाती हैं मीठा गाना,
पशु-पक्षी परमात्मा को साक्षी मान जीवन में,
चलते हैं प्रतिदिन नीड़ो से अपने ढूँढने को दाना ।

आज समय कुछ, कल कुछ और होगा जीवन में,
क्यों अवसाद में रह आज के ÷आनंद÷ को घटाना,
करने आए हैं हम कुछ श्रेष्ठतम् कर्म जीवन में,
क्यों शिकायतों से फिर दिल को अपने दुखाना ।

हर जीव की अधूरी है प्यास जन्म-मृत्यु के फेरे में,
लोभ मद मत्सर के बंधनों में क्यों ध्येय भूलाना,
माफ़ करने की व्यवस्था की हैं प्रभु ने जीवन में,
हमें सुपात्र बन सभी पापों का प्रायश्चित हैं करना ।

मेरा-तेरा ये तुच्छ विचार आते हैं भ्रमित मन में,
हमें इससे कोसो आगे जा परम तत्व को है पाना,
पुण्य प्रताप से पाई है मनुष्य योनि इस जन्म में,
सुसंस्कारों से इस जीवन को कृतार्थ हैं बनाना ।

बाल मृत्यु का कलंक

महाराष्ट्र में कुपोषण की गंभीर समस्या ने एक बार फिर सिर उठा लिया है। पिछले पांच महीनों में महाराष्ट्र में कुपोषण के कारण 65 बच्चों की मौत हो चुकी है और इस शर्मनाक वाकये के बावजूद सरकार इन बाल मौतों को गंभीरता से लेती नजर नहीं आ रही है। राज्य के दूर-दराज इलाकों में आदिवासी बच्चे कुपोषण के कारण मर रहे हैं और गैंडे की खाल वाली सरकार आंखें मूंदे बैठी है। क्या सरकार सोचती है कि गरीब परिवारों के बच्चों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है? कुपोषण के कारण होनेवाली ये बाल मौतें सरकार की निष्क्रियता का शिकार हैं और इसीलिए मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में इन बाल मौतों को गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार को बुरी तरह से लतो ा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर के ा प्रहार करते हुए कहा, 'सरकार की अक्षमता के कारण पिछले पांच महीनों में 65 बच्चों की बेवजह मौत हो चुकी है और सरकार का इस मामले में रवैया अभी भी बेहद गैर-जिम्मेदाराना है।' न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटील की पीठ ने न केवल सरकार को फटकार लगाई, बल्कि लोक स्वास्थ्य, आदिवासी विकास, महिला एवं बाल कल्याण और वित्त विभागों के प्रमुख सचिवों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का भी आदेश दिया। इन सभी प्रमुख सचिवों को 24 नवंबर को अदालत में पेश होना है और 65 बच्चों की मौत के बाबत हलफनामे भी पेश करने हैं। अगर कुपोषण और बाल मृत्यु दर की बे ती घटनाओं से सरकार का दिल नहीं पसीज रहा हो तो किसी को हंटर हाथ में ले लेना चाहिए। लाश बन चुकी संवेदनहीन सरकार पर यह चाबुक चलाने के लिए अदालत को धन्यवाद देना चाहिए। इन दिनों यह आरोप आम है कि अदालतें सरकार विरोधी रुख अपनाने से कतराती हैं। न्यायिक सक्रियता के आरोप अब बंद हो गए हैं। उलटे, न्याय के बजाय सरकार की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिशें ज्यादा हो रही हैं। दबाव के ऐसे माहौल में भी, यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बात है कि अदालत कम से कम कुपोषण जैसे सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दे और सरकार को उसके कर्तव्य का बोध कराए। बेशक, यह सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि बंडू साने, डॉ. राजेंद्र बर्मा, डॉ. अभय बंग जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मेलघाट में कुपोषण से बच्चों की मौतों को रोकने के लिए जनहित याचिका दायर करके 'जागृति' की भूमिका निभाई, जिसके कारण बच्चों की मौतों का यह भयावह मामला और इसके प्रति सरकार की उदासीनता अदालत तक पहुंच पाई। सात महीने पहले के आंके ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में 1 लाख 82 हजार 443 बच्चे कुपोषित थे। इनमें से लगभग 31 हजार बच्चे कुपोषण की तीव्र श्रेणी के पाए गए, जबकि मध्यम श्रेणी में 1.5 लाख बच्चे कुपोषित पाए गए। फिर कुपोषण अब आदिवासी इलाकों तक सीमित नहीं है, राज्य में कुपोषित बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या, 16,344, मुंबई के उपनगरीय इलाकों में दर्ज की गई है। जब कुपोषण का संकट इतना विकट हो तो सरकार को कुपोषण से ले ने के लिए आहार, स्वास्थ्य और पोषण के त्रिसूत्र का उपयोग करना चाहिए, लेकिन अगर सरकार और अधिकारी लोगों के स्वास्थ्य की तुलना में स्वास्थ्य विभाग के टेंडरों में अधिक रुचि रखते हैं तो वे कुपोषण की समस्या से वैससे निपटेंगे? राज्य में कुपोषण और बाल मृत्यु दर के आंके महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य के लिए शर्मनाक हैं। जब मेलघाट और राज्य के अन्य दूर-दराज के इलाकों में कुपोषण के कारण ते प-ते प कर बच्चे मर रहे हैं तो सरकार वास्तव में क्या कर रही है? क्या आदिवासी इलाकों के गरीब लोग, पो ा, वाडी और बस्तियों में रहनेवाले आम लोग महाराष्ट्र की प्रजा नहीं हैं? अगर हम इन पो ों में बच्चों को इतना अच्छा खाना भी नहीं दे सकते कि वे कम से कम जिंदा रह सकें तो सरकार में शामिल हुक्मरानों को पहले यह मान लेना चाहिए कि वे बदनसीब, नकारे मनहूस हैं। कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु एक कलंक है। क्या सरकार समृद्ध महाराष्ट्र के माथे पर लगे इस कलंक को हमेशा के लिए मिटाने के लिए कुछ करेगी?

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

CMYK

दैनिक घटती-घटना के वरिष्ठ लेखक डॉ. राजकुमार मिश्र का निधन

सरगुजा ने खो दिया अपनी पहचान का एक स्तंभ...

- चर्चित साहित्यकार,निर्भीक पत्रकार और सेवाभावी चिकित्सक डॉ. राजकुमार मिश्रा का निधन...
- दुःख भरे दिन...पत्रकारिता ने अपना प्रहरी खो दिया...
- पत्रकारिता की तेजस्वी कलम और होम्योपैथी चिकित्सा के जादूगर डॉ. राजकुमार मिश्र नहीं रहे...
- अचानक निधन से पत्रकारिता जगत,साहित्य समाज और प्रदेश में शोक की लहर...दैनिक घटती-घटना अखबार परिवार ने कहाः 'एक युग का अंत'

-घटती-घटना समाचार-

सरगुजा,17 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)। सरगुजा क्षेत्र के चर्चित साहित्यकार,निर्भीक पत्रकार और सेवाभावी होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. राजकुमार मिश्रा का बीती रात निधन हो गया वे 76 वर्ष के थे,उनके निधन से साहित्य,पत्रकारिता और चिकित्सा–तीनों ही क्षेत्रों में अपूरणीय शोक छा गया है,सरगुजा ने आज अपने एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया,जिसने अपने जीवन से अधिक अपनी कर्मशीलता और सेवा-भाव से क्षेत्र को प्रभावित किया। वैसे ख्याति प्राप्त पत्रकार,संवेदनशील लेखक और होम्योपैथी उपचार विधा में विशेष पहचान रखने वाले डॉ. राजकुमार मिश्र का यूँ अचानक निधन हो जाना न केवल उनके परिवार के लिए,बल्कि पूरे सरगुजा संभाग और दैनिक घटती-घटना समाचार परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है,उनकी विदाई एक ऐसे अध्याय का अंत है,जिसने पत्रकारिता,समाज और लोगों के जीवन में अमिट छाप छोड़ी,डॉ. मिश्र वर्षों तक दैनिक घटती-घटना अखबार से जुड़े रहे, उन्होंने राजनीति,समाजिक,संस्कृति,आस्था,व्यवस्था और जन-सरोकार से जुड़े विषयों पर सैकड़ों लेख लिखे,उनकी लेखनी न तो किसी दबाव में झुकती थी,न ही किसी प्रलोभन में डगमगाती थी। उनका हर लेख तथ्यपूर्ण,तर्कसंगत और गहरी सामाजिक समझ से भरा होता था। उन्हें पढ़ने वाले आज भी उनके शब्दों की सटीकता, सरलता और प्रभाव को याद करते हैं।

साहित्य जगत में राष्ट्रीय पहचान,1975-1990 का स्वर्णिम दौर

डॉ. मिश्रा ने वर्ष 1975 से 1990 के बीच अपनी सशक्त, संवेदनशील और सामाजिक यथार्थ से जुड़ी कहानियों के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्रीय पहचान बनाई,उनकी अनेक कहानियाँ देशभर में मंचित हुई,प्रकाशित हुई और पुरस्कृत भी रहीं, उनका कथाकार व्यक्तित्व इतना मजबूत था कि वे हिंदी साहित्य के समकालीन लेखकों की अग्रिम पंक्ति में गिने जाते थे,अंबिकापुर आकाशवाणी पर उनके लिखे नाटक,कहानियां और रूपक आज भी सरगुजा क्षेत्र की सांस्कृतिक स्मृतियों में जीवित हैं उन्हें सरगुजा के उन विरले साहित्यकारों में गिना जाता है,जिन्होंने अपनी कलम से पीढ़ियों को प्रभावित किया।

डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ सरगुजा में सेवा का प्रारंभ

70 के दशक में डॉक्टरी की पढ़ाई पूर्ण कर वे पहली बार सरगुजा आए और होम्योपैथी चिकित्सा सेवा प्रारंभ की, उनकी चिकित्सा शैली और मरीजों के प्रति आत्मीयता ने उन्हें 'सेवाभावी चिकित्सक' की पहचान दिलाई उनका उपचार हजारों परिवारों के लिए सहारा और विश्वास का नाम था।

पत्रकारिता में साहस,सच्चाई और निर्भीकता का दूसरा नाम

सरगुजा में रहते हुए ही उन्होंने पत्रकारिता में कदम रखा और बहुत जल्द अपनी निष्पक्षता,तेज लेखनी और निर्भीक रिपोर्टिंग के कारण अलग पहचान बनाई, सत्ता प्रशासन–समाज–किसी का भय नहीं,सिर्फ सत्य और जनता के प्रति निष्ठा यह उनकी पत्रकारिता की सबसे बड़ी विशेषता थी,उनके लेखों में सामाजिक सरोकार प्रमुख थे,अन्याय,भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और जनसमस्याओं पर उनकी स्पष्ट और ईमानदार टिप्पणी को क्षेत्र के लोग आज भी मिसाल मानते हैं,उनकी बेबाक लेखनी ने सरगुजा पत्रकारिता को नई दिशा दी और कई युवा पत्रकारों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बने।

अचानक बिगड़ी तबीयत, प्रयासों के बावजूद जीवन यात्रा थम गई...

डॉ. मिश्रा पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे,बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की,लेकिन वे जीवन की अंतिम लड़ाई हार गए, उनका जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं,बल्कि एक विचार,एक युग और एक संवेदनशील लेखनी का शांत हो जाना है।

भरा-पूरा परिवार पीछे छोड़ गए...

उनके परिवार में तीन पुत्र, एक पुत्री सहित अनेक नजदीकी परिजन, प्रियजन, मित्र और शुभचिंतक शामिल हैं,समाज,साहित्य और पत्रकारिता जगत में उनके जाने से शोक की लहर फैल गई है, अंबिकापुर, सरगुजा और आसपास के क्षेत्र में सुबह से ही उनके निधन की खबर ने लोगों को गहरे दु:ख में डूबा दिया।

एक ऐसा लेखक जिसकी लिखी बातें दिल और दिमाग दोनों में उतर जाती थी...

डॉ. मिश्र की लेखन शैली जितनी सौम्य थी, उतनी ही धारदार भी,राज्य स्तर की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी, सामाजिक बुराइयों पर उनका लेख जनमानस का दर्पण होता था,धार्मिकआस्था और समाज-चिंतन पर उनके लेखों में दर्शन,अनुभव और सादगी का अद्भुत मेल रहता था,उन्होंने अपने लेखन से कई ऐसे मुद्दों को उजागर किया,जिन्हें समाज अनदेखा कर देता था,उनके शब्द केवल रिपोर्ट नहीं होते थे,वे समाज की आत्मा को झकझोरते थे।

होम्योपैथी उपचार में उनका व्यक्तित्व...

'एक उम्मीद ' - डॉ. मिश्र केवल पत्रकार नहीं थे, वे एक अनुभवी होम्योपैथी विशेषज्ञ भी थे,उनके उपचार से लाभान्वित लोगों की संख्या अनगिनत है,लोग उन्हें डॉक्टर से ज्यादा 'परिवार के अपने व्यक्ति' मानते थे,वे इलाज नहीं, भरोसा देते थे–और यही भरोसा उन्हें अलग पहचान दिलाता था।

दैनिक घटती-घटना परिवार के लिए यह केवल नुकसान नहीं,एक व्यक्तिगत पीड़ा है...

डॉ. मिश्र का अखबार से संबंध केवल लेखक-पाठक तक सीमित नहीं था वे सुझाव देते थे,मार्गदर्शन करते थे, गलतियों पर डांटते थे और सही कार्य पर प्रशंसा भी करते थे,उनका स्नेह,अपनापन,और निस्वार्थ योगदान इस संस्थान की नींव को मजबूती देते रहे,उनके निधन से जैसे घटती-घटना का एक स्तंभ गिर गया हो।

स्मृति-खंड 'वह कलम जो सच लिखने के लिए बनी थी'... -

समाज के कमजोर वर्ग की आवाज उठाना,प्रशासन और व्यवस्था की कमियों को बेबाकी से लिखना,राजनीति की परतों को समझ कर विश्लेषण करना,आस्था और संस्कृति को वैज्ञानिक नजर से देखना और सबसे बढ़कर–सत्य के पक्ष में खड़े रहना,यह सब डॉ. मिश्र की लेखनी की पहचान थी, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी जनहित और निष्पक्षता उनकी मेहनत, ईमानदारी,संयम और संवेदनशीलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हैं। 'डॉ. राजकुमार मिश्रा का जीवन संघर्ष,सेवा और सृजन की अद्वितीय यात्रा थी उनकी स्मृति सदैव अमर रहेगी।' ओम् शांति।

हेड कॉन्स्टेबल ने वकील और बेटे को पीटा...एफआईआर दर्ज

कार मोड़ने के दौरान विवाद,पत्नी से भी अभद्रता एसएसपी ने पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)। अंबिकापुर में गाड़ी मोड़ने के दौरान इंडिकेटर नहीं देने के विवाद पर हेड कॉन्स्टेबल और उसके साथियों ने वकील और उसके बेटे की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही पत्नी से भी अभद्रता की। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक,इस मामले में पुलिस ने हेड कॉन्स्टेबल सहित चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घटना के विरोध में ब्राह्मण समाज और वकील संघ ने नाराजगी जताई है। हालांकि,सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल ने हेड कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल, फुंदुरडिहारी के रहने वाले वकील राजेश तिवारी का बेटे राहुल को पोर्च के अंदर खड़ा करने के लिए गाड़ी मोड़ने के लिए शनिवार की रात करीब 11 बजे पटेलपारा तिराहे तक गया था। गाड़ी मोड़कर जब वह वापस घर की ओर जा

रहा था, उसी दौरान वहां चारपहिया वाहन सवार गांधीनगर थाने का हेड कॉन्स्टेबल संतोष कश्यप अपने एक साथी के साथ पहुंचा।

गाड़ी मोड़ने के दौरान विवाद पर की मारपीट : संतोष कश्यप ने राहुल की कार के सामने अपनी गाड़ी लगा दी और बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी मोड़ने को लेकर गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर हेड कॉन्स्टेबल और उसके साथी ने राहुल के साथ मारपीट की। राहुल ने फोन पर सूचना अपने पिता को दी। वहीं संतोष की सूचना पर उसके दो अन्य साथी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। राजेश और उनकी पत्नी संध्या तिवारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान संतोष और उसके साथी राहुल को पीट रहे थे। बीच-बचाव करने पर राजेश के साथ भी हेड कॉन्स्टेबल और उसके तीन साथियों ने मारपीट की। बीच बचाव करने पहुंची पत्नी को उन्होंने धक्का दे दिया, जिससे उनके सिर में चोटें आईं और वह बेहोश हो गई। मारपीट में वकील का बायां पैर फ्रैक्चर हो गया।

हेड कॉन्स्टेबल सहित 4 के खिलाफ एफआईआर : रात में ही मामले की सूचना सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल को दी गई। एसएसपी के निर्देश पर गांधीनगर पुलिस ने अपने ही थाने के हेड कॉन्स्टेबल संतोष कश्यप सहित उसके तीन साथियों के खिलाफ धारा 296, 351(3), 115(2),3(5) के तहत एफआईआरदर्ज किया है। मामले में हेड कॉन्स्टेबल को लाइन अटैच करने का आदेश दिया गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंबिकापुर दौरा...जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)। 20 नवम्बर को अंबिकापुर में आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। यह अवसर सरगुजा संभाग के लिए ऐतिहासिक है,क्योंकि 37 वर्षों बाद यह पहला मौका है जब कोई राष्ट्रपति इस क्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू का आगमन विशेष महत्व रखता है,जो इस क्षेत्र की जनजातीय संस्कृति और गौरव को मान्यता देने वाला प्रतीक बन गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन स्थल पीजी कॉलेज ग्राउंड में लगभग 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे इस कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे सरगुजा संभाग में इस ऐतिहासिक मौके को लेकर विशेष उत्साह और जोश है। लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेताब हैं और उनके मन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर विशेष आस्था है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। रविवार की शाम को आदिम जाति विकास, कृषि विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम स्थल पीजी

कॉलेज ग्राउंड का निरीक्षण किया। इससे पहले, वित्त और सरगुजा प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने भी स्थल निरीक्षण किया और कार्यक्रम के आयोजन में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की स्थिति की समीक्षा की। मंत्री नेताम ने विशेष रूप से कार्यक्रम स्थल पर बैठने की व्यवस्था,पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन

राष्ट्रपति के आगमन के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। गांधी स्टेडियम में तीन हेलीपैड बनाए गए हैं,जहां से राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगी। सुरक्षा के लिहाज से पिछले तीन से चार दिनों से स्टेडियम में आम नागरिकों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। शहर भर में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं, और एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) की टीम मंगलवार को अंबिकापुर पहुंचेगी, ताकि वह पूरी सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम की तैयारी का जायजा ले सकें।कार्यक्रम के केवल तीन दिन शेष रह जाने के बाद,प्रशासन ने अंतिम तैयारियों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विशेष रूप से राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल से लेकर गांधी स्टेडियम तक पहुंचने वाले मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। मंगलवार को एसपीजी टीम अंबिकापुर पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्था की समीक्षा करेगी। इस महत्वपूर्ण दिन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं ताकि यह कार्यक्रम सफल और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।

यातायात डायवर्सन एडवाइजरी

कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने और यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा ट्रैफिक डायवर्सन एडवाइजरी जारी की गई है। 20 नवम्बर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुछ प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। आकाशवाणी चौक से पॉलिटेक्निक कॉलेज गेट नं-1 (रिंग रोड) और घड़ी चौक से किसान राइस मील मोड़ (मेन रोड) तक यातायात पूर्णत: बंद रहेगा। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। मनेन्द्रगढ़ रोड और बनारस रोड से आने वाली बसें और फोर व्हीलर को साई मंदिर तिराहा, महापौर मार्ग,रावत रेजीडेंसी तिराहा, कन्या परिसर रोड, गंगापुर मोड़ होते हुए अपने गंतव्य पर भेजा जाएगा। बलरामपुर रोड और प्रतापपुर रोड से आने वाली बसें और फोर व्हीलर रिंग रोड होते हुए प्रतापपुर चौक, लरंगसाय चौक, चाँदनी चौक, भारतमाता चौक,बस स्टैंड से अपने गंतव्य पर जाएंगी। रायगढ़ और बिलासपुर रोड से आने वाली बसें और फोर व्हीलर रिंग रोड होते हुए भारतमाता चौक, बिलासपुर चौक, नया बस स्टैंड, गंगापुर मोड़ होते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचेंगी। भारी वाहनों को सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आपातकालीन सेवा वाहन को विशेष अनुमति प्राप्त होगी।

दो बाइक की भिड़ंत में दो युवक की मौत

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)। अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर स्थित गांधीनगर थाना क्षेत्र के चठिरमा बैरियर के पास सोमवार की दोपहर आने सामने दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। यहां जांच के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार रवि पिता विरेंद्र सोनगरा थाना क्षेत्र के ग्राम सकलपुर का रहने वाला था। वह अंबिकापुर में रहकर मजदूरी का काम करता था। सोमवार की दोपहर अपने साथी मुकेश के साथ बाइक से करवां सूरजपुर जा रहा था। अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर स्थित गांधीनगर थाना क्षेत्र के चठिरमा बैरियर के पास पहुंचा ही था कि एक अन्य बाइक से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक बाइक सहित सड़क पर फेंका गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

जिला प्रभारी सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह पहुंचे बच्चो के बीच,शिक्षा व्यवस्था की ली जानकारी

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)। लोक निर्माण विभाग एवं जिला प्रभारी सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर सरगुजा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था,छात्रों की उपस्थिति और विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर श्री विलास भोसकर भी उपस्थित रहे।

कस्तुरबा आवासीय विद्यालय झिरमिटी में औचक निरीक्षण : जिला प्रभारी सचिव डॉ. सिंह ने सबसे पहले कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय, झिरमिटी का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय पहुंचने पर छात्राओं ने स्कूल बैंड की धुन पर उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं से संवाद करते हुए भोजन व्यवस्था, आवासीय सुविधाएं,पढ़ाई की स्थिति,पुस्तकें और अध्ययन सामग्री, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली।जिला प्रभारी सचिव डॉ. सिंह ने छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने उज्जवल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं जिला प्रभारी सचिव ने शासकीय माध्यमिक शाला जजगा का निरीक्षण किया।

यहां उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति एवं अटेंडेंस प्रक्रिया, कक्षा संचालन, अध्ययन सामग्री की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने विद्यालय में शिक्षण

गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा बच्चों की सीखने की क्षमता में सुधार लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

अधिवक्ता,उनकी पत्नी व बेटे को प्रधान आरक्षक ने अपने भाई व अन्य के साथ मिलकर की मारपीट

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

प्रधान आरक्षक अपने भाई व साथियों के साथ मिलकर रविवार की रात अधिवक्ता राजेश तिवारी,उनकी पत्नी व बेटे के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। अधिवक्ता की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने प्रधान आरक्षक,उसके भाई व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अधिवक्ता राजेश तिवारी पटेलपारा फुंडूरडिहारी के रहने वाले हैं। रविवार की रात करीब 11 बजे राजेश तिवारी का पुत्र राहुल तिवारी कार को गेट के अंदर पोर्च मं खड़ा करने के लिए वाहन को बैक करने घर के समीप तिराहा के पास गया था। तिराहे के पास वाहन को मोड़ ही रहा था कि प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप और उसके साथ एक अन्य लडक़ा अपने वाहन को राहुल तिवारी के वाहन के सामने अड़ा दिया और गाली गलौज करते हुए वाहन से खींचकर राहुल तिवारी के साथ मारपीट करने लगा। धक्का दिए जाने से

कार का चक्का नाली में चला गया। इस दौरान राहुल तिवारी ने मोबाइल से फोन कर अपने पिता को जानकारी दी। अधिवक्ता राजेश तिवारी पत्नी के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर प्रधान आरक्षक व उसके साथी को वापस भेज दिए। इसके बार राजेश तिवारी पत्नी के साथ घर वापस जा रहे थे और बेटे को बोले की गाड़ी लेकर आए। वह घर पहुंचे भी नहीं थे कि प्रधान आरक्षक अपने भाई संदीप कश्यप व दो अन्य के साथ पुनः मौके पर पहुंचकर राहुल तिवारी के साथ मारपीट करने लगे। उसने आवाज देकर पिता को बताया। राजेश तिवारी पत्नी के साथ पुनः मौके पर पहुंचे तो सभी ने मिलकर इन दोनों के साथ भी मारपीट की है। मारपीट से अधिवक्ता का पैर टूट गया है और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई है। अधिवक्ता ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी संतोष कश्यप, संदीप कश्यव व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

समाज में आक्रोश,एसपी को ज्ञापन

सरगुजा संभागीय सर्व ब्राह्मण समाज ने पुलिसकर्मी हवलदार संतोष कश्यप की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। राजेश अग्रवाल सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं। सामाज द्वारा चेतावनी दी गई है कि 24 घंटे के भीतर प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप की गिरफ्तारी नहीं होती, तो मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दिन हेलीपैड पर बड़ा धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। समाज ने आरोप लगाया कि एक पुलिसकर्मी द्वारा ऐसा अपराध करना विभागीय शपथ का उल्लंघन और कानून-व्यवस्था की अवहेलना है।

बीएलओ घर-घर जाने के बजाए मतदाताओं को अपने पास बुलाकर कर रहे एसआईआरःटीएस सिंहदेव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण को लेकर हो रहे कार्यों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय, राजीव भवन में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सोमवार को ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष एवं मंडल अध्यक्षों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया है। सांगठनिक ब्लॉक अध्यक्ष एवं वहां नवगठित मंडलों के अध्यक्षों सहित कांग्रेस के मोर्चा, विभाग एवं प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को विशेष गहन पुनरिक्षण, एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी मतदाता का नाम इस प्रक्रिया के बीच न छूटे। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने आगे कहा कि प्रशासन की ओर से घर-घर में दस्तक देकर हर व्यक्ति तक फार्म पहुंचाने की जिम्मेदारी बीएलओ को दी है। इन्हें घर में कोई मिले या न मिले,कम से कम तीन बार पहुंचना है। इसके बाद भी कई जगह से जानकारी मिल रही है कि कुछ बीएलओ घर-घर पहुंचने के बजाय एक जगह बैठक करके संबंधित मतदाताओं को एक जगह बुला रहे हैं। इनका हर घर में पहुंचना नहीं हो रहा है। पार्षदों को फार्म थमाने जैसी बातें भी सामने आ रही है। इसकी जानकारी उनके माध्यम से निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के लिए उपलब्ध कराए जा रहे फार्म को भरना आसान नहीं है। वे स्वयं इस फार्म को भरने के बाद भी इस बात को लेकर चिंतित हैं,कि उन्होंने अपना फार्म सही भरा है या नहीं,नई मतदाता सूची में उनका नाम होगा या नहीं। मतदाता सूची प्रकाशन होने के बाद ही पता चलेगा कि कितने मतदाताओं का नाम जुड़ा या हटा। ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं को और भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

मतदाता के फोटो के बैकग्राउंड को लेकर भी भ्रम की स्थिति है। फोटो देने की अनिवार्यता नहीं, जैसी बातें भी सामने आ रही है। सिंहदेव ने कहा कि निर्वाचन आयोग को जिस प्रक्रिया को स्वयं पूरा करना था,उसका बोझ मतदाताओं पर डाल दिया है। इसे दोषपूर्ण पहलू ही कहा जाएगा कि जो मतदाता शारीरिक रूप से विद्यमान है,वह फार्म भरने के लिए परेशान हो रहा है। भारत के नागरिकता की पहचान किसे है,किसे नहीं है,इसका परीक्षण निर्वाचन आयोग को स्वयं कराना था। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक,जेपी श्रीवास्तव, मधु दीक्षित,हेमंत सिन्हा,अनूप मेहता सहित अन्य उपस्थित थे।

विकसित भारत की सपना को साकार करेंगे,बीपीएस पोया

-संवाददाता-
सूरजपुर,17 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग सूरजपुर द्वारा आयोजित पांच दिवसीय आदिवासी युवा सोशल मीडिया क्रिएटर, संवैधानिक कैरियर मार्गदर्शन एवं आत्मरक्षा गोटूल आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के अंतिम दिवस की शुरुआत अतिथियों के स्वागत गीत,अक्षत तिलक लगाकर स्वागत से हुई। मुख्य प्रशिक्षक अश्वनी कांगे (कांकेर-बस्तर) ने पेसा कानून,पंचायती राज, संविधान तथा ग्राम सभा की ताकत पर युवा प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा– मावा नाटे मावा

राज–हमारे क्षेत्र में हमारा राज। कार्यक्रम में जितेंद्र चंद्रवंशी ने युवाओं को जीवन में संघर्ष और मेहनत को सफलता की आधारशिला बताया। पूर्व सीएम एचओ डॉ. आर.एस. सिंह ने युवाओं से आत्मविश्वास बनाए रखने,नकारात्मक बातों को अनदेखा कर शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की अपील की। मंगलम उरांव (SECL, उप प्रबंधक) ने आदिवासी समुदाय को एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। कुमार गौरव व खुशबू कुमारी ने पांच दिनों तक आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया तथा अंतिम दिन उसका प्रभावी प्रदर्शन कर उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। बीपीएस पोया,जिला अध्यक्ष - सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग,ने बताया, 'आदिवासी पिछड़े युवाओं को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देकर हम प्रत्येक युवा को उनकी रुचि के अनुसार आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे आदिवासी पिछड़े वर्ग के युवा विकसित भारत की नींव में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।'उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण जिला से लेकर विकासखंड और ग्राम स्तर तक विस्तारित होगा,ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के हर युवा को अवसर मिल सके। समापन समारोह में सभी प्रतिभागी युवाओं को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए तथा अतिथियों को स्मृति-कलम देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित अतिथि एवं प्रमुखजन डॉ. अजय मरकाम,विजय सिंह ठाकुर जगत मरकाम (KBKS),मनीष सिंह धुर्वे (GPM युवा प्रभाग जिला अध्यक्ष),विनय पावले, सत्यप्रकाश पैकरा,सतबीर सिंह, कर्मचंद आयाम,चंद्र विजय आरमो, बिरसा मुंडा,विजय सिंह मरपच्ची, उमंत्रीलाल बियार,राजा क्षितिज उइके,कवल बिहारी टेकाम, गीता पण्डो अंजली सिंह उईके, विशाखा पैकरा मेहरनोश बड़ा, गौरीशंकर नेताम अमरकली पैकरा सहित समाज के अनेक प्रमुखजन, कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे।

सूरजपुर के तहसील लटोरी में 45 बोरी अवैध धान जप्त,कार्रवाई जारी

-संवाददाता-
सूरजपुर,17 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार जिले में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में तहसील लटोरी क्षेत्र में बिना वैध दस्तावेज के पिकअप वाहन से 45 बोरी धान का अवैध परिवहन किया जा रहा था।

राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त कार्यवाही में के दौरान वाहन चालक की जांच की गई ।कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाने पर पिकअप वाहन सहित धान को जप्त कर चौकी लटोरी की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी सीजन के दौरान अवैध परिवहन एवं भंडारण पर सख्त निगरानी जारी रहेगी और ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई की जाएगी।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ समापन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, के प्रागंण में दिनांक 10 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक महाविद्यालय के विधि विभाग एवं आई क्यू एस सी द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यशाला के छह दिवस में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित विभिन्न विषयों पर 10 तकनीकी सत्र संचालित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से रिसोर्स पर्सन आयें एवं अपने व्याख्यान तथा प्रयोगात्मक प्रसतूती द्वारा प्रतिभागियों को ज्ञानवर्धन कियें। कार्यशाला में संभाग के अन्य महाविद्यालय तथा देश अन्य राज्यों से लगभग 200 प्रतिभागी ऑफलाईन एवं ऑनलाईन माध्यम शामिल हुए। समापन समारोह में मुख्य अतिथि

डॉक्टर वी. के. सिंह, भूतपूर्व संकाय प्रमुख, शासकीय राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय,अंबिकापुर थें। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव ने की, स्वागत उद्बोधन आई क्यू एस सी समन्वयक एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार सिंन्हा द्वारा किया गया। साथ ही महाविद्यालय के स्वशासी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर दीपक सिंह ने कार्यक्रम के सफलता पर अपनी विचार रखें। कार्यशाला रिपोर्ट एवं धन्यवाद ज्ञापन आयोजन सचिव एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार द्वारा रखा गया। कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर राजकमल मिश्रा, डॉक्टर एस. एन. पाण्डेय,डॉक्टर आर. पी. सिंह तथा कार्यक्रम के विभिन्न समितियों के सदस्यों एवं सभी सहायक प्राध्यापकों की रही।

देश की एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन

माँ समलेश्वरी महामाया मंदिर,केनापारा से बस स्टैंड विश्रामपुर तक पदयात्रा कर जिलेवासियों ने दिया एकता का संदेश

-संवाददाता-
सूरजपुर,17 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

देश के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज सूरजपुर में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। भारत माता की जय, सरदार पटेल अमर रहे,वंदे मातरम् के उद्घोष के साथ ढोल-मंजीरे की मंगल ध्वनि से रैली निकाली गई। ''यूनिटी मार्च'' कार्यक्रम का आयोजन माँ समलेश्वरी महामाया मंदिर, केनापारा से बस स्टैंड बिश्रामपुर तक किया जायेगा। पदयात्रा प्रातः 09:00 बजे माँ समलेश्वरी महामाया मंदिर, केनापारा-तेलाईकछार शुरू हुई जोकि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल,कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल,व्हीएम कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग जयनगर से होते हुए अम्बेडकर चौक बिश्रामपुर, शिवनंदनपुर वार्ड क्रमांक 12 से होते हुए बस स्टैंड बिश्रामपुर में सम्पन्न हुई। लगभग 08 से 10 किलोमीटर की दूरी तक निकली रैली में शहरवासियों का उत्साह देखने

लायक था। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुये मंत्री श्रीमती रजवाड़े ने कहा कि 'यह वर्ष हमारे लिए गर्व का वर्ष है। हम छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल्पना से यह राज्य अस्तित्व में आया और आज हम सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं,जिन्होंने 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड

भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश की सेवा में अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित किया। उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी,यह उनके त्याग,समर्पण और राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक है। हमारा देश धन संचय करने वालों का नहीं, त्याग करने वालों का आदर करता है। उन्होंने सभी को पदयात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। सरगुजा लोकसभा सांसद श्री चिंतामणी महाराज ने अपने उद्बोधन मे कहा कि आज का दिन हम सबके लिए एक गर्व का क्षण है। सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण आज भारत एक सशक्त और अखंड राष्ट्र के रूप में खड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी से संकल्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया।

स्कूली छात्रा से अनाचार के आरोपी व्याख्याता को जशपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

पीड़ित नाबालिग बालिका आरोपी शिक्षक के घर में रहकर करती थी काम,स्कूली छात्रा को अकेली पाकर आरोपी गिरधारी राम यादव करता था, छेड़ छाड़ व दुष्कर्म,परेशान हो बालिका ने आरोपी शिक्षक के घर से भाग, घटना के संबंध में बताया परिजनों को

-संवाददाता-
जशपुरनगर,17 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

जशपुर कोतवाली क्षेत्र में शहर के एक सरकारी स्कूल की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी एमएलबी कन्या शाला के व्याख्याता को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी अपराध दर्ज होने के बाद से फरार था। पीड़ित बालिका की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली जशपुर में किया गया था, आरोपी शिक्षक के विरुद्ध बी एन एस की धारा 74,75,64(2)(रू),65(1) एवं पॉस्को एक्ट की धारा 6,8 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिक्षक गिरधारी राम यादव घटना दिनांक से था फरार, पुलिस कर रही थी लगातार तलाश,

पुलिस सादी वर्दी में आरोपी के घर व मोहल्ले पर भी रखी हुई थी नजर, पुलिस के दबाव में अन्यत्र भागने के फिराक में था आरोपी, जैसे ही कपड़े व रुपए लेने घर पहुंचा, पुलिस की टीम ने धर दबोचा। दिनांक 14.11.2025 को जशपुर के एक स्कूल में अध्ययनरत् 16 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने परिजनों के साथ थाना सिटी कोतवाली जशपुर में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी,कि वह जुलाई 2024 से आरोपी गिरधारी राम यादव के यहां रहकर घरेलू काम करती थी,इसके साथ ही वह जशपुर के एक स्कूल में पढ़ाई भी करती है। इस दौरान आरोपी गिरधारी राम यादव ने घर में रहने के दौरान अकेला पाकर ,वह कई बार छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म किया है। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के द्वारा,आरोपी शिक्षक की पता साजी हेतु कई पुलिस टीम गठित की गई थी, जिनके द्वारा आरोपी शिक्षक गिरधारी राम यादव के छिपने की संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी,साथ ही पुलिस की टेक्निकल टीम भी आरोपी शिक्षक गिरधारी राम यादव के संभावित लोकेशनों को ट्रेस कर रही थी व एक पुलिस की टीम सादी वर्दी में 24 घंटे आरोपी शिक्षक के मोहल्ले व घर पर नजर रखी हुई थी, कि इसी दौरान आरोपी गिरधारी राम यादव जैसे ही अपने घर आया , व पुलिस की सादी वर्दी की टीम ने तत्काल आरोपी शिक्षक को उसके घर से धर दबौचा। आरोपी शिक्षक पुलिस के लगातार दबाव के कारण,अपने घर से कपड़े व रुपए लेकर कहीं भागने के फिराक में था। पुलिस की पूछताछ पर आरोपी गिरधारी राम यादव के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया है, मामले में पुलिस की कार्यवाही जारी है, आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जावेगा।

सरगुजा के दूरदराज गांवों में सडक़ की मार झेलगी में ढोकर अस्पताल पहुंचाई गर्भवती किशोरी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

जिले के कई दूरदराज गांवों में सडक़ों की बदहाली और अव्यवस्था से लोग खासे परेशान हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाओं और बीमार मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में यह समस्या लगातार चर्चा में रहती है, और कई बार इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें मरीजों को झेलगी में ढोकर एंबुलेंस तक लाया जाता है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कदनई सुगाझरिया में एक बार फिर इसी प्रकार की एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। माझी जनजाति की एक गर्भवती किशोरी को 3 किलोमीटर तक झेलगी (खाट) में लादकर एंबुलेंस तक पहुंचाया गया। यह घटना सोमवार को घटी,जब किशोरी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। पहले तो परिवार ने महतारी एंबुलेंस को फोन किया, लेकिन सडक़ के अभाव में एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद, मजबूरीवश परिजनों ने गर्भवती किशोरी को झेलगी में लादकर मुख्य मार्ग तक लाने का निर्णय लिया। जब परिवार ने पथरीले और ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर यात्रा शुरू की,तो किशोरी को

प्रसव पीड़ा में और अधिक बढ़ोतरी महसूस होने लगी। हालांकि, रास्ते में ही उसका प्रसव हो गया। इसके बावजूद, परिजनों ने घबराए बिना उसे झेलगी में ढोते हुए एंबुलेंस तक पहुंचाया। फिर,महतारी एंबुलेंस के माध्यम से उसे बतौली शांतिपारा अस्पताल पहुंचाया गया,जहां दोनों जच्चा और बच्चा का इलाज शुरू किया गया। चिकित्सकों के अनुसार, दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। ग्राम कदनई सुगाझरिया के ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में बारिश के दिनों में यह समस्या और भी बढ़ जाती है। बारिश के कारण पथरीला रास्ता और भी अधिक दुर्गम हो जाता है, जिससे मरीजों और गर्भवती महिलाओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसे मरीजों को झेलगी में ढोकर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है। इसके कारण कई गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान भी जा चुकी है। सरकार से लोगों की अपील है कि इस क्षेत्र में सडक़ निर्माण पर जोर दिया जाए ताकि आम नागरिकों को इस तरह की गंभीर समस्याओं का सामना न करना पड़े और उनकी जान को खतरे से बचाया जा सके। यह घटना स्पष्ट रूप से यह साबित करती है कि सडक़ सुविधाओं की कमी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न केवल असुविधाजनक,बल्कि कभी-कभी जानलेवा भी हो सकती है।

आदित्य विद्या मंदिर की स्कूल बस सेवा ठप हिण्डाल्को प्रबंधक की अनदेखी अभिभावक नाराज

-संवाददाता-
सामरी,17 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

हिण्डाल्को जन सेवा ट्रस्ट खान प्रभाग द्वारा संचालित आदित्य विद्या मंदिर स्कूल की बस सेवा इन दिनों सुर्खियों में है। अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल बस सेवा लगातार अनियमित बनी हुई है,जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ रहा है। अभिभावकों के अनुसार, पिछले कई हफ्तों से बस सेवा सप्ताह में 4-5 दिनों तक ही

उपलब्ध हो रही है। कई बार तो बस लगातार दो-दो दिन तक नहीं आती, जिससे बच्चे सुबह-सुबह बस स्टॉप पर घंटों इंतजार कर वापस घर लौटने को मजबूर हो जाते हैं। आज भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली, जहां कई बच्चे बस न आने के कारण स्कूल नहीं पहुँच सके। अभिभावकों का कहना है कि हिण्डाल्को प्रबंधन द्वारा संचालित इस बस सेवा की लापरवाही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के समान है। बच्चों की नियमितता और शैक्षणिक प्रदर्शन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं छोटे बच्चों को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता भी बढ़ गई है। कई अभिभावकों ने बताया कि बस समय पर न आने के कारण उन्हें रोज़ाना अपनी दिनचर्या बिगाड़कर बच्चों को खुद स्कूल छोड़ना पड़ता है। मजदूरी, खेती-किसानी और नौकरी करने वाले अभिभावकों के लिए यह स्थिति बेहद परेशानी भरी है। बस का कोई तय समय न होना और बिना पूर्व सूचना के रूट छोड़ देना व्यवस्थागत कमजोरियों की ओर इशारा करता है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि बस चालक और ईंधन से जुड़ी कुछ आंतरिक समस्याओं की शिकायतें भी समय-समय पर सामने आती रही हैं, लेकिन प्रबंधन द्वारा कभी भी इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बनी रहने से अभिभावकों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने भी प्रबंधन को चेताया है, कि शिक्षा जैसी मूलभूत व्यवस्था से जुड़ी लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

CMYK

जिला अस्पताल की लापरवाही उजागर,

जांच आदेश में अधीक्षक को क्यों छोड़ा गया ?

- क्या अधीक्षक नियमों के ऊपर? प्रसूता का मामला उजागर होते ही बचाव के प्रयास!
- सरकारी अस्पताल की बदइंतज़ामी, डॉक्टर अनुपस्थित, अधीक्षक पर कार्यवाही ठंडी
- प्रसूता के साथ अस्पताल में अत्याचार, ड्यूटी में लापरवाही पर अधीक्षक जवाबदेह क्यों नहीं?
- महिला का जीवन जोखिम में, डॉक्टर गायब, अधीक्षक की प्रशासनिक विफलता उजागर

जिला अस्पताल बैकुंठपुर में प्रसूता घंटों तड़पती रही, डॉक्टर नहीं पहुंचीं, परिजन ऑटो से ले गए प्राइवेट अस्पताल

जिला चिकित्सालय अधीक्षक की भूमिका पर उठे सवाल, कार्यवाही से दोषियों को बचाने की कोशिश या जिम्मेदारी तय होगी?

-रवि सिंह-

कोरिया,17 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

जिला अस्पताल बैकुंठपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर उजागर हुई है। बीती रात एक प्रसूता महिला गंभीर प्रसव पीड़ा में घंटों तड़पती रही,लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के नहीं आने से उसका ऑपरेशन नहीं हो सका, मजबूर परिजन आधी रात से लेकर सुबह तक इंतजार करने के बाद महिला को ऑटो में बिठाकर प्राइवेट अस्पताल ले जाने मजबूर हुए। घटना ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं, ड्यूटी शेड्यूल और निगरानी जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, परिजनों का आरोप है कि रात 1 बजे प्रसूता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दर्द बढ़ने पर जब परिवार ने ड्यूटी डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर ने आने में असमर्थता जताई। रात भर इंतजार के बाद भी डॉक्टर या विशेषज्ञ टीम नहीं पहुंची,जिला अस्पताल बैकुंठपुर में प्रसूता से जुड़े इस संवेदनशील मामले ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है,जांच समिति बनाकर मामला शांत करने की कोशिश की जा रही है,लेकिन अधीक्षक की जिम्मेदारी तय किए बिना यह जांच अधूरी मानी जाएगी,अब सवाल यह है कि क्या वास्तविक दोषियों पर कार्यवाही होगी या फिर इस बार भी फाइलों में मामला दबा दिया जाएगा?

सीएमएचओ,अधीक्षक जांच अधिकारी सभी विदेशों से पढ़कर आए डॉक्टर,क्या मामले के पटाक्षेप के लिए जांच अधिकारी खास को बनाया गया ?

जिले के स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ,अधीक्षक जिला चिकित्सालय,साथ ही जांच अधिकारी सभी विदेशों से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त किए हैं,सभी आज जिम्मेदार पदों पर हैं और जिले में पदस्थ उनसे योग्य और अनुभवी साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सक इनके अधीन कार्य कर रहे हैं,क्या जांच अधिकारी बनाए जाने के पीछे भी जांच के दौरान मामला पटाक्षेप किए जाने का प्रयास है।

अधूरी संवेदनशीलता, टूटता भरोसा... जिला अस्पताल पर फिर उठे सवाल...

जिला अस्पताल में ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस घटना ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है क्या इस मामले में केवल जांच समिति बनाकर जिम्मेदारी से बचा जा सकता है?

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया जांच आदेश, लेकिन अधीक्षक मामले पर चुप्पी क्यों ?

ध्यान देने वाली बात यह है कि जांच आदेश में जिला चिकित्सालय अधीक्षक का नाम शामिल नहीं है,ऐसा क्यों है यह बड़ा सवाल है,अधीक्षक को जांच के दायरे से बाहर क्यों रखा गया यह एक सवाल है।

क्या अधीक्षक की जिम्मेदारी नहीं? यही सबसे बड़ा सवाल अब जनता में चर्चा का विषय है

- क्या जिला चिकित्सालय के अधीक्षक इस व्यवस्था के प्रमुख नहीं?
- क्या ड्यूटी रोस्टर, डॉक्टरों की उपलब्धता और समय पर सेवाएं सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी नहीं?
- क्या अधीक्षक को केवल इसलिए बचाया जा रहा है कि मामला प्रशासनिक दृष्टि से संवेदनशील है?
- जांच आदेश में उन्हें क्यों शामिल नहीं किया गया?

जिला अस्पताल बैकुंठपुर में प्रसूता महिला घंटों तड़पती रही
डॉक्टर ने कहा- 'मैं अभी नहीं आ पाऊंगी'

जिम्मेदारी तय किए बिना कैसे मिलेगा न्याय ?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्यवाही करना समस्या का समाधान नहीं है, अस्पताल की संपूर्ण व्यवस्था अधीक्षक के नियंत्रण में होती है यदि डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे तो यह सीधा प्रशासनिक विफलता का मामला है।

जांच समिति गठित,पर सवालों की लंबी सूची

प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति तो बना दी है, लेकिन जनता का भरोसा तभी लौटेगा जब जिला चिकित्सालय के अधीक्षक की भूमिका की भी जांच होगी, ड्यूटी डॉक्टर पर भी स्पष्ट कार्यवाही होगी, और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

परिजनों की पीड़ा, 'अगर देर होती तो... ?'

परिवार का कहना है कि यदि वे समय रहते प्राइवेट अस्पताल नहीं जाते,तो प्रसूता और बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। सरकारी अस्पताल में भरोसा था,लेकिन घंटों तड़पते रहने के दौरान कोई डॉक्टर नहीं आयाज्यह सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है।

मुख्यालय में नहीं रहते पीडब्लूडी के अफसर-कर्मचारी,जनता परेशान

सरकारी क्वार्टर होने के बाद भी रोज़ाना दूसरे जिलों से आना-जाना,कामकाज ठप, आदेश हवा में...

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,17 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

शासन द्वारा बार-बार दिए जा रहे निर्देशों के बावजूद नगर के कई सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय में नहीं रहते, इसका सीधा असर आम जनता के कामकाज पर पड़ रहा है, लेकिन इस मनमानी पर न कार्रवाई हो रही है,न ही कोई जवाबदेही तय की जा रही है। शिकायतें कई बार उच्चाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई गईं, मगर हर बार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिला। जिले में दौरे पर आने वाले प्रभारी मंत्री, विभागीय मंत्री और कलेक्टर स्पष्ट निर्देश देते हैं कि सभी अधिकारी अपने-अपने मुख्यालय में रहें, पर हालात जस के तस हैं।

पीडब्लूडी में मनमानी सबसे ज्यादा, सरकारी क्वार्टर होने के बाद भी बाहर से आना-जाना

पीडब्लूडी विभाग के अफसरों की मुख्यालय से गैरहाजिरी अब एक खुला राज बन चुकी है,एसडीओ राजू वर्मा,सरकारी क्वार्टर आवंटित,फिर भी प्रतिदिन सरगुजा से आना-जाना,नतीजा फील्ड निरीक्षण और जनता से जुड़े काम प्रभावित,सब-इंजीनियर प्रमोद गुप्ता रामानुज नगर में अधिकृत क्वार्टर,लेकिन सूरजपुर से रोज़ सफर कार्यस्थल पर उपलब्धता कम,सब-इंजीनियर सुधीर बड़ा,प्रतापपुर में आवंटित सरकारी निवास, फिर भी सरगुजा से आते-जाते,सब इंजीनियर पंकज जिला मुख्यालय में है अधिकृत विभागीय कार्य प्रगति मानों ठप्प,इनकी अनुपस्थिति से निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग, शिकायतों का निस्तारण और ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।

आम जनता की शिकायत,ऑफिस में अधिकारी मिलते ही नहीं...

नागरिकों का कहना है कि अधिकारी मुख्यालय में नहीं ठहरते, अचानक आवश्यकताओं में संपर्क नहीं हो पाता, सरकारी कामों में अनावश्यक देरी,आपात स्थितियों में भी साहब शहर में नहीं हैं का जवाब मिलता है

प्रशासन की निष्क्रियता भी सवालों के घेरे में...

जब उच्च स्तर से लिखित और मौखिक दोनों तरह के आदेश मौजूद हैं,तो फिर इन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या विभागीय अधिकारियों को पूरी छूट दे दी गई है? या फिर मुख्यालय में न रहने का यह प्रचलन प्रशासन की नज़र में अपराध नहीं? मुख्यालय में न रहने वाले अफसरों की यह मनमानी सिर्फ शासन के आदेश का उल्लंघन नहीं,बल्कि जनता के अधिकारों से खिलवाड़ है,जरूरत अब औपचारिक चेतावनी नहीं, कड़ी कार्रवाई की है,ताकि जनता को राहत मिले और विभागों का कामकाज पटरी पर लौटे।

मारवाड़ी युवा मंच ने लगाया कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर, 76 को लगे हाथ-पांव

-संवाददाता-

सूरजपुर,17 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच व भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति झारखण्ड के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन मंच की सूरजपुर व संस्कृति शाखा के द्वारा किया गया। जिसमें पैर,हाथ के साथ कैलिपर्स,बैशाखी,छड़ी,कान की मशीन का वितरण मंच की ओर से संपन्न हुआ। 14 नवम्बर को प्रारंभ हुए शिविर में लगभग 100 से उपर दिव्यांगों का पंजीयन किया गया,जिसमें 63 को पैर,13 को हाथ तथा 5 को कैलिपर्स लगाए गए। मानवीय मूल्यों के कर्तव्यों का निवर्हन करने के साथ दुर्घटनाओं में अपने हाथ व पैर गंवा चुके या जन्म से ही दिव्यांग लोगों के लिए मंच का यह शिविर आत्मविश्वास लौटाने और उनके चेहरों की खुशी वापस लाने का माध्यम बना। मंच के अध्यक्ष सुमित मित्तल व शिविर के संयोजक विकास जैन ने बताया कि स्थानीय अग्रोहा भवन में उक्त आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से संस्था के सदस्यों ने दिव्यांगों का पंजीयन कर उनके पैर व हाथों का माप लिया और स्थल पर ही जयपुर फूट बनाकर प्रदान किए गए। जिसमें सूरजपुर जिले के साथ कोरिया,सरगुजा,जशपुर व बलरामपुर जिले के दिव्यांगजनों ने शिविर का सीधा लाभ लिया। शिविर को सफल बनाने में मंच के सुनील अग्रवाल,मुकेश गर्ग,अंकुर गर्ग, स्वयं गोयल, गौरिश जिंदल, संस्कार अग्रवाल,यश अग्रवाल,अंकित अग्रवाल,प्रणव अग्रवाल सहित संस्कृति शाखा की प्रज्ञा अग्रवाल, लहर मित्तल सहित दोनों शाखाओं के सदस्य सक्रिय थे। वहीं नगर के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एसआरपीआर के संचालक राहुल अग्रवाल व हॉस्पिटल की टीम का पूरे शिविर में विशेष योगदान रहा।

लोगों ने किया मंच का आभार व्यक्त

मारवाड़ी युवा मंच के इस शिविर का लोगों ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हाथ व पैरों के लिए वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बाहर जा पाने में असमर्थ हैं तथा कई-कई वर्षों से राह देख रहे थे। जब उन्हें शिविर की जानकारी मिली तो वे शिविर में पहुंचकर निःशुल्क पैर व हाथ का माप देकर वहीं पर बनने की प्रक्रिया देखी और शरीर के उक्त अंग को प्राप्त करने के बाद कईयों के आंखों से भी खुशी के आंसू थे। अनेक दिव्यांगजनों व उनके परिजनों ने मंच के इस जनसेवी कार्य के लिए आभार व्यक्त किया।

बैशाखी व दूसरे के सहारे आये लोग खुद चलकर गए

शिविर के दौरान पहले दिन का आलम यह था कि दिव्यांगजन या तो बैशाखी के सहारे आये थे या फिर उनके परिजन उन्हें ढोकर लाये थे और जब उनके पैरों का माप हुआ और चलकर बिना किसी सहारे के गए तो उनका आत्मविश्वास भी देखते ही बनता था। अनेक दिव्यांगजनों ने तो दो दिन तक उनको लगे पैरों पर स्थल में ही चलकर अपने आपको मजबूत भी किया व बिना बैशाखी व बिना सहारे के सड़क पर भी जाकर चहल कदमी की।

न्यायालय तहसीलदार अंबिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः, 202511020700027

विषयः-अ-27 मामले की श्रेणीः-राजस्व सनः-2025-26

थोर प.ह.नं.00027
पक्षकारों का विवरणः-
आवेदक पक्षकार-मोहित राम, सनमेत राजवाड़े,मुली बाई,बह्मलो बाई,रामबाई,
अनावेदक पक्षकार-मोहित राम, सनमेत राजवाड़े,मुली बाई,बह्मलो बाई,रामबाई,

ईश्तहार

आवेदक सनमेत राजवाडे पति स्व0 सोहित राजवाडे, निवासी ग्राम थोर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम थोर स्थित खसरा नंबर 22, 24 / 1, 27/1, 31/ 2. 377/1, 380/1, 381/1, 395/1, 544/2, 545/2, 546/1, 546/3, 548/1, 552/2 कुल खसरा नंबर 14 कुल रकबा 2.792 हे0 भूमि को उभयपक्ष के मध्य में 1/2 अंश में बटवारा किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 08.12.2025 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03/11/2025 को जारी किया जाता है।

सील — उमेश्वर सिंह बाज तहसीलदार,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा0प्र0क0/...../अ-6 /2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सज्जन कुमार अग्रवाल पिता स्व. धनसी राम अग्रवाल, निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक एवं अनावेदक भजन कुमार अग्रवाल आ.स्व. धनसी राम अग्रवाल, निवासी चोपड़ापारा अम्बिकापुर संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की शीट नं. 03, मोहल्ला केदारपुर नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लॉट नं. 1205/3 रकबा 303.6 वर्गमीटर भूमि है। अनावेदक द्वारा उक्त भूमि में से अपने हक व हिस्से की भूमि का पंजीबद्ध हकत्याग विलेख दिनांक 25 सितम्बर 2025 का निष्पादन आवेदक के पक्ष में किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध हकत्याग विलेख दिनांक 25.09.2025 के आधार पर आवेदक द्वारा उक्त भूमि के नजूल अभिलेख में स्वयं का नाम दर्ज कराने हेतु पंजीबद्ध हकत्याग विलेख दिनांक 25.09.2025 की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू.रा.संहिता 1959 के तहत् प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 05/12/2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक-11/11/2025 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अंबिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः, 202510020700073

विषयः-अ-27 मामले की श्रेणीः-राजस्व सनः-2025-26

लक्ष्मीपुर प.ह.नं.00023
[78/2(0.0280 हे.)]
पक्षकारों का विवरणः-
आवेदक पक्षकार-विजय कुमार सिंह पिता मुनेश्वर अंकिता पिता विजय, ना.बा. रितिका ना. बा. अनन्या,
अनावेदक पक्षकार-विजय कुमार सिंह पिता मुनेश्वर अंकिता पिता विजय, ना.बा. रितिका ना. बा. अनन्या,

ईश्तहार

आवेदक विजय कुमार सिंह आ0 मुनेश्वर, निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम लक्ष्मीपुर स्थित खसरा नंबर 78/2 रकबा 0.028 हे0 भूमि को उभयपक्ष के मध्य में 1/2 अंश में बटवारा किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 22.12.2025 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 14/10/2025 को जारी किया जाता है।

सील — उमेश्वर सिंह बाज तहसीलदार, अंबिकापुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क0 202510021700061 /अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिवकुमार सरकार आ. स्व. धीरेन्द्रनाथ, निवासी ग्राम किशुननगर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम किशुननगर स्थित भूमि भूमि खसरा नंबर 477 / 2 रकबा 0.470 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखों में वसीयतनामा दिनांक 05.06.2025 के आधार पर, वसीयतकर्ता विनोदनी सरकार का नाम विलोपित कराकर अपना नाम दर्ज कराने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 21.11.2025 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 29/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-02

तहसील पटना में राजस्व माफिया सक्रिय ?

नवगठित नगर पंचायत पटना में अवैध प्लाटिंग का बड़ा खेल !

तहसीलदार पटवारी पर अवैध प्लाटिंग का बड़ा खेल चलाने का आरोप...छोटे झाड़ मद की भूमि के लगभग 70 टुकड़े बेच डालेःसूत्र

बीजेपी सरकार की पुरानी व्यवस्था फिर लागू

उल्लेखनीय है कि बीजेपी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में भी पाँच डिसमिल से कम भूमि के उपखंड और रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में कांग्रेस सरकार ने इस रोक को हटा दिया था, जिसके बाद पांच डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री बड़े पैमाने पर होने लगी थी। अब पुनः बीजेपी सरकार ने पुराने नियम को लागू करते हुए इसे कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

विधानसभा में पारित भू-राजस्व संहिता विधेयक 2025 लागू

राज्य सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 पारित किया है,नए प्रावधान के तहत किसी भी स्थिति में कृषि भूमि को ऐसा उपखंड बनाकर नहीं बेचा जा सकेगा,जिसका क्षेत्रफल पाँच डिसमिल से कम हो,उप-पंजीयक कार्यालय में ऐसे किसी दस्तावेज को पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

क्या जिला प्रशासन लेगा संज्ञान ?

क्या होगी नियम विरुद्ध खरीदी-बिक्री पर रोक? यदि सूत्रों द्वारा बताई गई बातें सत्य हैं, तो यह पूरा मामला बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग और नियमों की खुली धज्जियां उड़ाने जैसा प्रतीत होता है, अब सवाल उठ रहा है कि क्या जिला प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेकर जाँच कराएगा? क्या अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग और बिक्री पर रोक लगेगी? क्या कूटरचना कर भूमि बेचने वालों पर कार्रवाई होगी? सूत्रों का कहना है कि पूरा मामला अवैध प्लाटिंग का है और इसे नियमों के विरुद्ध बेचा जा रहा है।

अंगद की तरह जमे पटवारी बाबू, ट्रांसफ़र के बाद भी पैसे देकर वापस उसी हल्के में...

20 जुलाई से जिले में सख्ती शुरू,सभी उप पंजीयकों को आदेश जारी

पटवारी तहसील की मिलीभगत की आशंका,छोटे झाड़ जंगल मद भूमि को बेचने की तैयारीःसूत्र

-रवि सिंह-
कोरिया/पटना,17 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

नवगठित नगर पंचायत पटना में अवैध प्लाटिंग का गंभीर मामला सामने आया है, सूत्रों के अनुसार पटना गायत्री मंदिर चौक में मुख्य पांडवपारा रोड के किनारे भूमि की गुपचुप प्लाटिंग कर बेचने का काम शुरू हो चुका है,इस कथित अवैध गतिविधि में राजस्व विभाग के तहसील कार्यालय से लेकर पटवारी स्तर तक की सहमति बताई जा रही है,मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जिस जमीन की प्लाटिंग की जा रही है,वह छोटे झाड़ जंगल मद की भूमि बताई जा रही है जिसकी खरीदी-बिक्री शासन द्वारा प्रतिबंधित है। इसके बाद भी भूमि को खंड-खंड कर प्लॉट बनाकर बेचने का प्रयास किया जाना नियमों की खुली अवहेलना माना जा रहा है, तहसील पटना एक बार फिर भ्रष्टाचार के बड़े अड्डे की तरह सुर्खियों में है। सूत्रों का दावा है कि तहसीलदार और पटवारी की मिलीभगत से गांव पटना में अवैध प्लाटिंग का करोड़ों का खेल जोरों पर चल रहा है। आरोप है कि दलालों के माध्यम से पैसों की मोटी कमाई कर छोटे झाड़ मद की प्रतिबंधित भूमि को खरीद-फरोख्त के खुले मैदान में बदल दिया गया है।

सूत्रों का कहना है कि छोटे झाड़ जंगल मद श्रेणी की भूमि को टुकड़ों में बांटकर बेचा जा रहा है, जबकि ऐसी भूमि की खरीदी-बिक्री पर शासन ने स्पष्ट रोक लगा रखी है, बताया गया कि जमीन बेचने वालों के पास न तो कॉलोनाइज़र लाइसेंस है और न ही 5 डिसमिल से कम भूमि बेचने की अनुमति, आरोप है कि इस पूरे मामले में तहसील कार्यालय और पटवारी की मिलीभगत है,अब बड़ा प्रश्न यह है कि क्या जिला प्रशासन इस नियम विरुद्ध प्लाटिंग और अवैध बिक्री पर कार्रवाई करेगा, या फिर मामला यूं ही दबा दिया जाएगा? सूत्रों ने यह भी बताया कि पटना में पदस्थ पटवारी को तीन साल से अधिक समय हो चुका है, जबकि नियम के अनुसार इतने लंबे समय तक एक ही जगह पदस्थ रहना सामान्य प्रक्रिया नहीं है, आरोप यह भी है कि पटवारी द्वारा छोटे झाड़ङ्कजंगल मद की भूमि का नामांतरण तक कर दिया गया है, जिसमें गायत्री चौक क्षेत्र की जमीन का नामांतरण सबसे चर्चित मामला माना जा रहा है, सूत्रों के अनुसार, प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का नामांतरण करना स्वयं में गंभीर अनियमितता है,और यह पूरा मामला राजस्व विभाग के भीतर गहरी मिलीभगत की ओर संकेत करता है।

नियम-कानून को दरकिनार कर विवादित भूमि का नामांतरण कराने का आरोप

राजस्व विभाग में नियमों की खुली धज्जियाँ उड़ाने का गंभीर मामला सामने आया है जानकारी के अनुसार, पूर्व तहसीलदार पटना द्वारा किए गए कई विक्रय पत्रों और नामांतरणों को न्यायालय ने अवैध प्लाट में होने का आधार बताते हुए ऑनलाइन नामांतरण प्रक्रिया में खारिज कर दिया था, इन मामलों में न्यायालय की स्पष्ट टिप्पणी थी कि भूमि अवैध प्लाटिंग की श्रेणी में आती है, इसलिए इसका नामांतरण राजस्व पुस्तिका में दर्ज नहीं किया जा सकता, नियम कहते हैं की राजस्व पुस्तिका-6 के अनुसार, यदि नामांतरण खारिज हो जाता है, तो संबंधित पक्ष को अपीली अधिकारी,अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी होती है,अपीली अधिकारी के निर्णय के बाद ही आगे की प्रक्रिया संभव होती है लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा दिख रहा है, ऑनलाइन खारिज, फिर तहसीलदार ने ऑफलाइन नामांतरण किया सूत्रों के अनुसार, जिन प्रकरणों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर ऑनलाइन सिस्टम ने खारिज कर दिया था, उनका ऑफलाइन आवेदन लेकर पुनः नामांतरण कर दिया गया।

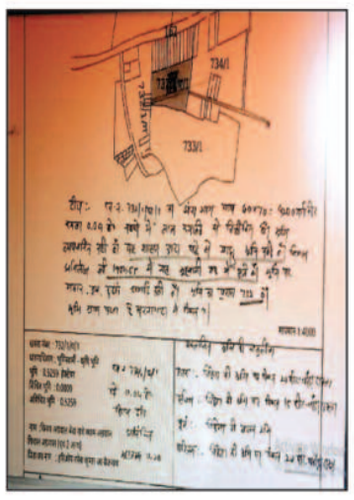

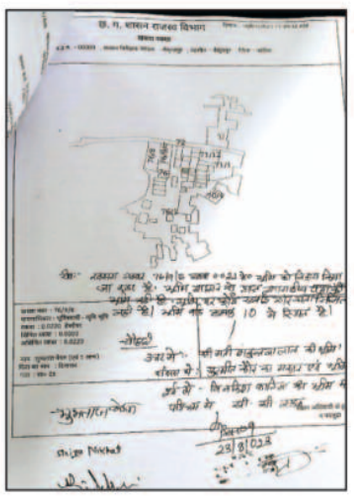

खसरा नंबर 732, प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि फिर भी लगभग 70 टुकड़ों में बेच डालीःसूत्र

सूत्र बताते हैं कि ग्राम पटना स्थित खसरा नंबर 732, जो मिसल 1946-47 में छोटे झाड़ मद दर्ज है...जिसकी बिक्री पर रोक है प्लाटिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध है कॉलोनाइज़र लाइसेंस अनिवार्य है इसके बावजूद 70 प्लॉट में बांटकर दी गई बिक्री पटना में खुलेआम की गई है, यह सब बिना अनुमति, बिना लाइसेंस और बिना राजस्व नियमों का पालन किए, सूत्रों का कहना है कि इस भूमि के कई हिस्सों का दायर्वसन भी कराया गया, जबकि पुराने रिकॉर्ड में यह भूमि हस्तांतरित होने योग्य ही नहीं।

खसरा नंबर 729,आदिवासी भूमि भी बेची गई ? लगभग 49 टुकड़े तैयार,गैरआदिवासियों के नामःसूत्र

सूत्र बताते हैं कि खसरा नंबर 729, जो मिसल 1946-47 में पर्व कुंवर गोंड (आदिवासी) के नाम से दर्ज है, आदिवासी भूमि होने के कारण विशेष अनुमति अनिवार्य परंतु इस भूमि को 49 टुकड़ों में बांटकर बिना अनुमति गैरआदिवासियों को बेच दिया गया, सूत्रों के मुताबिक अनुमति के कागजों पर डायवर्सन का नाम जरूर है,पर 1946-47 के छोटे झाड़ मद के असली रिकॉर्ड का उल्लेख ही नहीं,जिससे पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है।

5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री पूर्णतः बंद, 20 जुलाई से जिले में सख्ती शुरू,सभी उप पंजीयकों को आदेश जारी

जिले में कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बेचने और अवैध प्लाटिंग को बढ़ावा देने पर आखिरकार प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है,लंबे समय से पाँच डिसमिल से कम भूमि की रजिस्ट्री धड़ल्ले से की जा रही थी,जिससे अनियंत्रित और अवैध कॉलोनाइज़ेशन लगातार बढ़ रहा था। अब राज्य सरकार ने छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर सख्त रोक लगा दी है,जारी आदेश के अनुसार 20 जुलाई से जिले में पाँच डिसमिल (0.05 एकड़) से कम भूखंड की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी,सभी जिला पंजीयकों एवं उप पंजीयकों को इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं, शासन ने 5 डिसमिल (लगभग 2,178 वर्गफीट) से कम भूमि की खरीदी-बिक्री पर स्पष्ट रोक लगा रखी है,लेकिन पटना में कथित तौर पर इसी सीमा से नीचे छोटे-छोटे भूखंड बनाकर उनकी बिक्री की तैयारी की जा रही है,अब बड़ा सवाल क्या राजस्व विभाग इस मामले से अनभिज्ञ है? क्या पटवारी को इसकी जानकारी नहीं? या फिर पूरा मामला मिलीभगत का परिणाम है?

सवाल गंभीर,क्या पटना तहसील अवैध प्लाटिंग का केंद्र बन चुका है ?

जो आरोप सामने आए हैं,वे कई बड़े सवाल खड़े करते हैं,क्या तहसील और पटवारी कार्यालय जमीन माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है? क्या प्रतिबंधित भूमि को जानबूझकर प्लाटिंग योग्य दिखाया जा रहा है? क्या जिला प्रशासन को वास्तविक स्थिति छिपाई जा रही है? क्या राजस्व विभाग इस पूरे खेल से अनभिज्ञ है या मिलीभगत से आंखें मूंदे है?

जनता परेशान,कामकाज प्रभावित

एक ही क्षेत्र में वर्षों से जमे पटवारी-बाबुओं के कारण, दस्तावेज़ों में मनमानी, देरी और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, ग्रामीणों को आवश्यक नस्ती, नामांतरण, बंटवारा और गिरदावरी जैसे कार्यों के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं, कई स्थानों पर शिकायत है कि पुराने संपर्कों और जमावट के कारण लेन-देन की व्यवस्था पहले से भी मजबूत हो गई है।

अंगद की तरह जमे पटवारी-बाबू, ट्रांसफ़र के बाद भी पैसे देकर वापस उसी हल्के में...

प्रशासनिक सख्ती की खुली उड़ रही धज्जियाँ...जिले में वर्षों से एक ही स्थान पर जमा पटवारी और बाबू प्रशासन के आदेशों की खुली अवहेलना करते हुए अंगद के पाँव की तरह अपने हल्के और कार्यालय से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। विभाग द्वारा किया गया ट्रांसफर महज़ औपचारिकता बन गया है,क्योंकि कई कर्मचारी अपने स्थानांतरण के बाद भी पैसे और रसूख के बल पर कुछ ही दिनों में वापस अपने निज निवास ग्राम,हल्के या मनपसंद तहसील कार्यालय में आकर फिर बैठ जाते हैं, सूत्रों के अनुसार, ट्रांसफ़र के बाद ज्वाइनिंग कहीं और, पर ड्यूटी वहीं, यह खेल वर्षों से चलता आ रहा है, अधिकारी भी आँख मूंदकर इस व्यवस्था को सहन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबकी हिस्सेदारी की चर्चा खुलेआम होती है,ट्रांसफर नीति का मज़ाक सरकार द्वारा बनाई गई स्थानांतरण नीति का मैदान स्तर पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा,ट्रांसफर के आदेश जारी होते ही कर्मचारियों की एक टीम सक्रिय हो जाती है,और कुछ दिनों में फिर वही पुरानी कुर्सी,वही पुराना हल्का और वही पुराना खेल, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा? जनता लगातार मांग कर रही है कि,वर्षों से एक ही जगह जमे पटवारीङ्कबाबुओं की सूची सार्वजनिक की जाए, उनके अवैध पुनःस्थापना की जांच हो,और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ताकि राजस्व व्यवस्था में फैली यह जमावट संस्कृति समाप्त हो सके।

मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह पर कोरबा पुलिस की कठोर कार्रवाई

-संवाददाता-
कोरबा,17 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल कुमार पाठक के निर्देशन में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है,इसी क्रम में दीपिका पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रार्थी मोहम्मद असलम द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दीपिका स्थ्रष्टरु खदान से रोलर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किया गया है। उक्त रिपोर्ट में थाना दीपिका में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के पताशाजी के दौरान मूखबीर सूचना के आधार पर संदेही जय सिंह पटेल को पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ के दौरान अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एसईसीएल दीपका खदान से रोलर की चोरी के साथ-साथ दीपका थाना, कुसमुंडा थाना एवं सर्वमंगला चौकी क्षेत्र से मोटरसाइकिल की चोरी करना स्वीकार किया और आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर उपरोक्त 14 मोटरसाइकिल को बरामद कर जप्त किया गया है। आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उपरोक्त 7 आरोपियों 01 जयसिंह पटेल पिता मोहन सिंह पटेल उम्र 27 वर्ष निवासी 4 पर कोहड़िया थाना सिविल लाइन रामपुर 02 अनस खान पिता चांद

खान उम्र 24 वर्ष निवासी नया बस स्टैंड पाली थाना पाली 03 शिवचरण पिता स्वर्गीय जगन राम उम्र 31 वर्ष निवासी रेनापुर थाना दिपका 04 रामप्रसाद रोहिदास पिता किरीट राम उम्र 25 वर्ष निवासी झाबर थाना दिपका 05 लालजी यादव पिता स्वर्गीय राम सिंह यादव उम्र 30 वर्ष निवासी चैनपुर थाना दिपका 06 इमरान अंसारी पिता शमीम अंसारी उम्र 21 वर्ष निवासी ज्योति नगर दीपका 07 सुनील देवार पिता राजेंद्र देवर उम्र 25 वर्ष निवासी देवार पारा बलोदा जिला जांजगीर चांपा को अपराध क्रमांक 405/2025 धारा 303(2),317(2), 3(5) बी एन एस के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा गया है वही 06 नग चोरी के स्थ्रष्टरु के रोलर जप्त साथ ही 14 मोटरसाइकिल को भी किया गया जप्त।

ग्राम पंचायत मेड्रा में बन रही सीसी सड़क चढ़ रही है भ्रष्ट्राचार की भेंट

आखिर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में पदस्थ एसडीओ एवं इंजिनियर के कार्य काल की बनी सीसी सडक महज कुछ माह में ही धराशाई हो गई है ऐसा क्यों ?

क्या अधिकारी निर्माण का निरीक्षण करने का झूठा दावा करते हैं जिसका मूल रूप ग्राम पंचायत मेंड्रा में निर्मित सी सी सडक स्पष्ट बया कर रही ?

-राजेन्द्र शर्मा-
खड़गवां,17 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जनपद पंचायत खडगवां से महज पूर्व दिशा में ग्राम पंचायत मेड्रा स्थिति है जहा पर ग्रामीणों के विरोध के बाद भी गढहीनाला सी सी सडक निर्माण कार्य पूर्ण रूप से घटिया एवं गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किया जा रहा है इस सी सी सडक निर्माण कार्य में जिस मापदंड की गिट्टी का उपयोग किया जाना है वो नहीं किया जा रहा है जिसका विरोध ग्राम पंचायत के पंच के द्वारा निर्माण स्थल की सामाग्री और निर्माण कार्य का विडियो जारी कर स्पष्ट विरोध किया जा रहा है। इस सीसी सडक निर्माण कार्य के नाम पर ग्राम पंचायत मेंड्रा में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

जिम्मेदार जनपद पंचायत के अधिकारी एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के एस डी ओ एवं इंजिनियर इन घटिया निर्माण कार्य की शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय कार्यालय में बैठकर भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदारों को ही बढ़ावा दे रहे हैं। शासन से मिलने वाली राशि का निर्माण कार्य में बंदरबाट कर राशि को ठिकाने लगाने में लगे हैं। जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा हैं।

जनपद पंचायत खडगवां अंर्तगत ग्राम पंचायत मेंड्रा सीसी सड़क निर्माण कार्य के लिए राशि स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसका निर्माण कार्य गढहीनाला मार्ग पर होना है। लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत मेड्रा के मनमानी के कारण अपने चहेते ठेकेदार को सीसी सड़क निर्माण कार्य कराने का जिम्मा दिया था उक्त ठेकेदार ने घटिया एवं गुणवत्ता विहीन सीसी सड़क के निर्माण कार्य को अंजाम दिया जो सी सी सडक घटिया एवं गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किया जा रहा है विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं सी सी सड़क। इस सी सी सड़क की गुणवत्ता को प्रमाणित कर रहा है। सीसी सड़क में घटिया गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य में उपयोग की गई निर्माण सामाग्री है। वार्ड पंच का आरोप हैं कि उपयंत्री द्वारा सीसी सड़क निर्माण के दौरान निर्माण कार्यों की सही जांच नहीं की गई न ही निर्माण के समय मानिटरिंग की गई जिसके चलते इस तरह घटिया एवं गुणवत्ता विहीन सी सी सडक का निर्माण कार्य किया जा रहा है?

C M Y K

जैस्मिन का 37 साल बाद बदल गया है इतना लुक

साल 1988 में आई फिल्म वीराना की जैस्मिन याद हैं? भूतनी का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती के चलते बॉलीवुड पर राज करती थी,लेकिन अचानक फिल्मों से गायब हो गईं। अब 37 साल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

}} एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं एक्ट्रेस का वीडियो वायरल?
}} वीराना से पॉपुलर हुई थीं एक्ट्रेस जैस्मिन
}} इंडस्ट्री में जैस्मिन ने कीं सिर्फ तीन फिल्में
}} वीराना के बाद अचानक इंडस्ट्री से हो गई थीं गायब

कुछ अभिनेत्रियां हवा के झोंके जैसी आईं और फिर सिनेमा से हमेशा-हमेशा के लिए गायब हो गईं। वीराना मूवी की जैस्मिन भी उन्हीं में से एक हैं। भूतनी का किरदार निभाने वालीं जैस्मिन वीराना मूवी से रातोंरात स्टार बन गई थीं।
वीराना में अपनी अदाकारी ही नहीं, जैस्मिन ने अपनी खूबसूरती से लोगों को दीवाना बना दिया था। वीराना सफल हुई और

जैस्मिन को भी स्टारडम मिला लेकिन वह अचानक फिल्मों से गायब हो गईं।

13 साल की उम्र में किया था डेब्यू

जैस्मिन सिर्फ 13 साल की थीं, जब उन्होंने विनोद खन्ना के साथ फिल्म सरकारी मेहमान से डेब्यू किया था। फिर वह डाइवोर्स मूवी में भी दिखाई दीं। इन फिल्मों से ज्यादा उन्हें पहचान रामसे ब्रदर्स की फिल्म वीराना से मिली जिसमें उन्होंने एक भूतनी का किरदार निभाया था जो मर्दों को लुभाकर उनकी हत्या कर देती है।

जैस्मिन ने वीराना के बाद छोड़ी थी इंडस्ट्री

इस फिल्म के बाद हर ओर जैस्मिन के चर्चे होने लगे थे। इससे पहले उन्हें कोई बड़ी फिल्म मिलती, उन्होंने चुपके से इंडस्ट्री को गुडबाय कह दिया है। एक्ट्रेस कहां गईं, क्या कर रही हैं, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। मगर अब 37 साल बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है।

जैस्मिन का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ब्लू जींस और शर्ट पहनी महिला को जैस्मिन बताया जा रहा है। बॉलीवुड टेस्ट नाम के इंस्टाग्राम पेज ने इस वीडियो को शेयर किया है और कैप्शन लिखा है, वीराना की वायरल जैस्मिन एयरपोर्ट पर देखी गई। मगर बता दें कि जैस्मिन का ये वीडियो एआई से बनाया गया है।

अब कहां हैं वीराना की जैस्मिन?

साल 2017 में रामसे ब्रदर्स ने रिवील किया था कि मां के निधन के बाद जैस्मिन ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। वह मुंबई में ही रहती हैं। हालांकि, क्या करती हैं, इस बारे में किसी को नहीं पता।

धर्मेंद्र का हालचाल जानने पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा

पत्नी पूनम के साथ हेमा मालिनी से मिले,मुस्कुराती नजर आईं ड्रीम गर्ल

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस वक्त अपने घर पर डॉक्टरों की निगरानी में है और उनकी तबीयत में सुधार देखा जा रहा है। इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ एक्टर का हालचाल जानने के लिए पहुंचे।
शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी ने हेमा मालिनी से उनके घर जाकर मुलाकात की और धर्मेंद्र की हेल्थ के बारे में जानकारी ली।
इस मुलाकात की फोटो शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर की और लिखा- 'अपनी बेस्ट हाफ पूनम के साथ...हमारी डियर फैमिली फ्रेंड और बेहतरीन इंसानों में से एक, एक शानदार स्टार, बेहतरीन आर्टिस्ट, योग्य सांसद हेमा मालिनी से मिलने, उनका हालचाल जानने और शुभकामनाएं देने गया।
हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। हमने उनके पति, हमारे बड़े भाई और परिवार के सेहत के बारे में भी जानकारी ली।'
वहीं, इंस्टेंट बॉलीवुड के मुताबिक, हेमा मालिनी ने पत्रकार सुभाष के झा से धर्मेंद्र के हेल्थ पर बात की है। हेमा ने अपनी बातचीत में कहा...अभी तक वह ठीक हैं। हम एक-एक दिन करके स्थिति को संभाल रहे हैं।
वहीं, देओल फैमिली के एक करीबी ने सुभाष के झा को बताया कि अगर भगवान ने चाहा तो हम अगले महीने हम धरमजी और ईशा दोनों का जन्मदिन मनाएंगे। बता दें कि ईशा देओल को जन्मदिन 2 नवंबर को होता है लेकिन पिता की तबीयत ठीक होने तक उन्होंने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को पोस्टपोन कर दिया था।
एक्टर ने इस मुलाकात की दो फोटो शेयर की हैं। इनमें फोटोज में हेमा मालिनी स्माइल करते और रिलैक्स नजर आ रही हैं, जिससे ये साफ है कि धर्मेंद्र की तबीयत पहले से बेहतर है।
बता दें कि सांस लेने में दिक्कत के कारण एक्टर को 10 नवंबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इस बीच एक्टर के निधन की खबरें भी मीडिया में चली, जिस पर हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल ने गंभीर रिएक्शन दिया था।
धर्मेंद्र की तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें 12 नवंबर की सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया था। फिलहाल घर पर ही उनका इलाज चल रहा है। खबरों की माने तो एक्टर की तबीयत में सुधार हो रहा है और वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं।

दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी इस दिन देगी दस्तक

महिमा चौधरी-संजय मिश्रा की अनोखी बारात देखने को हो जाओ तैयार

महिमा चौधरी और संजय मिश्रा ने सिद्धांत राज सिंह की डायरेक्ट की हुई फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में साथ नजर आने वाले हैं, जो 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। महिमा चौधरी और संजय मिश्रा की अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी को लेकर काफी दिनों से सोशल मीडया पर जबरदस्त बज बना हुआ है। इसकी कास्ट फिल्म का प्रमोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जो दर्शक इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए खुशखबरी है। मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि यह फिल्म 19 दिसंबर, 2025 को थिएटर में आएगी। इस अनाउंसमेंट के साथ एक प्रमोशनल पोस्टर भी था, जिसमें लीड जोड़ी के बीच शादी के एक खास पल को दिखाया गया था।

महिमा चौधरी-संजय मिश्रा की अनोखी बारात

पोस्टर में संजय मिश्रा का कैरेक्टर माला पकड़े हुए महिमा चौधरी को प्यार से देख रहा है, जो ट्रेडिशनल दुल्हन के कपड़ों में शर्माते हुए दिख रही हैं। फिल्म के ऑफिशियल सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, शादी की घंटियां बज रही हैं! प्यार, परिवार और दूसरे मौके का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाइए। #दुर्लभप्रसादकीदूसरीशादी 19 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आ रही है।

दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी की कहानी

सिद्धांत राज सिंह के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी है, जो समाज और परिवार के दबाव में अपने विधुर पिता के लिए नई दुल्हन ढूंढने का इरादा कर लेता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कहानी प्यार, पारिवारिक रिश्तों और अचानक आने वाली कॉमेडी सिचुएशन के विषयों को दिखाती है। इस फिल्म में व्योम यादव, पलक लालवानी, प्रवीण सिंह सिसोदिया और श्रीकांत वर्मा जैसे कलाकार हैं, जो महिमा चौधरी और संजय मिश्रा के साथ अपने बेहतरीन किरदार निभाते नजर आने वाले हैं।

62 की उम्र में दूल्हा बने संजय मिश्रा

अपने रोल के बारे में बात करते हुए 62 साल के दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा,दुर्लभ प्रसाद एक ऐसा किरदार है जिसे आप उसकी सादगी और मासूमियत के लिए पसंद करेंगे। इमोशन के साथ कॉमेडी हमेशा खास होती है और इस फिल्म में दोनों ही भरपूर हैं। मैं दर्शकों को इस अनोखे दूल्हे और उसके उतने ही अनोखे सफर से मिलने के लिए उत्साहित हूं। रिलीज़ डेट अनाउंसमेंट से पहले, संजय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया था।

11 साल पहले ही डेब्यू कर चुका है महेश बाबू का बेटा

19 की उम्र में लगता है पापा की कार्बन कॉपी

महेश बाबू इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म वाराणसी को लेकर लगातार चर्चा में हैं। एसएस राजामौली के निर्देशन और प्रियंका चोपड़ा जोनास की मौजूदगी ने इस फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान दिला दी है। टीजर से लेकर ट्रेलर तक, वाराणसी ने वह उत्साह पैदा कर दिया है जो हाल के वर्षों में उनके किसी अन्य प्रोजेक्ट में कम देखने को मिला, लेकिन इन सबके बीच एक और नाम है जो शांत तरीके से स्पॉटलाइट में आ रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि महेश बाबू का बेटा गौतम घट्टामनेनी है। अब आखिर इनकी चर्चा क्यों हो रही है और ये करते हैं, ये जानने के लिए नीचे स्क्रोल करें।

गौतम की बढ़ती लोकप्रियता

गौतम सिर्फ महेश बाबू की शक्ल नहीं बल्कि उनकी पहचान की चमक भी अपने साथ लेकर चलते हैं। इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स उनके बढ़ते फैनबेस का प्रमाण हैं। साल 2006 में महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर के घर जन्मे गौतम बचपन से ही फिल्मी दुनिया के आकर्षण का हिस्सा रहे हैं। उनकी बहन सितारा पहले ही अपनी ज्वेलरी लाइन के साथ एक उभरती युवा सेलिब्रिटी बन चुकी हैं और गौतम भी तेजी से उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। बचपन से ही तय हो गया है कि गौतम भी पापा की तरह स्टार बनने की तैयारी में हैं।

खेल- समाचार

विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत 7 जनवरी से होगी

}} मुंबई में लीग मैच,बड़ौदा में फाइनल खेला जा सकता है,
}} 27 नवंबर को मेगा ऑक्शन

बड़ौदा,17 नवम्बर 2025। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। फाइनल 3 फरवरी को खेला जा सकता है। क्रिकबज के अनुसार, टूर्नामेंट के शुरुआती लीग मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जा सकते हैं, जिसने हाल ही में विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी की थी।
बाकी मैचों के लिए बड़ौदा को चुना गया है, जिसमें कोटांबी स्टेडियम में होने वाला फाइनल भी शामिल है। बड़ौदा में मुकाबले 16 जनवरी से शुरू हो सकते हैं, क्योंकि इसी मैदान पर 11 जनवरी को भारत-न्यूजीलैंड

का वनडे मैच खेलना है। टूर्नामेंट का पहला मेगा ऑक्शन इसी महीने 27 नवंबर को दिल्ली में होगा।

पिछले सीजन में 4 शहरों ने की थी मेजबानी

डब्ल्यूपीएल के तीसरे सीजन की मेजबानी 4 शहरों ने की थी। इनमें लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई और बड़ौदा शामिल थे। बीसीसीआई ने अभी फ्रेंचाइजी मालिकों को आधिकारिक रूप से नहीं बताया है कि इस बार मैच किस शहर में होंगे, लेकिन अनौपचारिक बातचीत में इन्हीं वेन्यूज पर चर्चा चल रही है।
टीमों को औपचारिक जानकारी 27 नवंबर को दिल्ली में होने वाली डब्ल्यूपीएल नीलामी के दौरान दी जा सकती है। इस बार भी मेजबानी के लिए वहीं 4 शहर- लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई और बड़ौदा ने दावेदारी पेश की थी। जिसमें मुंबई और बड़ौदा चुने गए हैं।

पिछले सीजन की चैंपियन मुंबई इंडियंस है,

डब्ल्यूपीएलको सबसे ज्यादा 2 बार मुंबई इंडियंस ने जीता है। टीम ने 2023 के पहले और 2025 के तीसरे सीजन में जीत हासिल की थी। 2024 के दूसरे सीजन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था।

जनवरी में क्यों हो रहा डब्ल्यूपीएल

अभी तक विमेंस प्रीमियर लीग के तीनों सीजन मार्च में खेले गए हैं। पहली बार टूर्नामेंट जनवरी में कराया जाएगा। इसके पीछे दो मुख्य वजह हैं-पुरुषों का टी-20 वर्ल्डकप फरवरी के पहले हफ्ते से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहा है, जो एक महीने चलेगा। जनवरी को डब्ल्यूपीएल की स्थायी विंडो माना जा रहा है, ताकि लीग की तारीखें किसी अन्य टी-20 लीग या ICC के फ्यूचर टूर प्रोग्राम से न टकराएं।

प्रीतम सिवाच,एचएआर और एएसए को जीत

करनाल,17 नवम्बर 2025। प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी, सोनीपत, एचएआर अकादमी और अनंतपुर स्पोर्ट्स अकादमी ने तीसरी हॉकी इंडिया-सब जूनियर महिला अकादमी चैंपियनशिप 2025 के तीसरे दिन अपने-अपने मैचों में शानदार जीत दर्ज की, जिसमें ज़ोन ए और बी में सभी पूलों में प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला। रितु रानी हॉकी अकादमी, मार्कंडेश्वर हॉकी अकादमी और खालसा हॉकी अकादमी (अमृतसर) ने भी महत्वपूर्ण जीत हासिल की। पूल ए में, प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी, सोनीपत ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ गुजरात - हॉकी अकादमी पर 11-0 की शानदार जीत के साथ दिन की शुरुआत की। कप्तान नैन्सी अरोहा ने चार गोल (23%, 45%, 56%, 58%) के साथ स्कोरिंग का नेतृत्व किया, जबकि दीया ने हैट्रिक (9%, 14%, 50%) बनाई। आरती (7%), मौकी (27%), संजना (32%) और अवनि (48%) ने एक-एक गोल किया।

पवन बर्तवाल ने अल्टीनबेक नूरसुल्तान को हराया

ग्रेटर नोएडा,17 नवम्बर 2025। भारत के पवन बर्तवाल (55 किग्रा) ने टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए, दूसरे वरीय और विश्व कप स्वर्ण पदक विजेता कजाकिस्तान के अल्टीनबेक नूरसुल्तान को सोमवार को शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में 5-0 से हराकर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पदक हासिल किया। उनके शानदार प्रदर्शन ने भारत के लिए एक और बेदाग दिन का नेतृत्व किया, जिसमें सुमित (75 किग्रा) और नवीन (90 किग्रा) ने भी प्रभावशाली जीत दर्ज करते हुए मेजबान देश के पदकों की संख्या सात पक्के कर दिए। पवन के लिए, यह क्षण 15 साल की मेहनत का नतीजा था। 2010 के दशक में मुक्केबाजी शुरू करने और चुपचाप रैंकों में ऊपर उठने के बाद, सर्विसेज के इस मुक्केबाज ने विश्व मंच पर शानदार प्रदर्शन किया।

ईडन की हार के बाद भी फाइनल खेल सकता है भारत

नई दिल्ली,17 नवम्बर 2025। भारतीय क्रिकेट टीम को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के हाथों 30 रन की हार मिली है। टीम इंडिया अपने गढ़ में 100 रन से भी कम पर लुढ़क गई। ईडन गार्डंस स्टेडियम में मिली इस हार ने टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने की उम्मीदों को भी झटका दिया है। अब डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने वाली दो टीमों में शामिल होने के लिए टीम इंडिया के पास महज 10 टेस्ट मैच बाकी हैं। ऐसे में उनके पास गलती के लिए बहुत कम मार्जिन बचा हुआ है। इसके चलते शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम इंडिया गणित की पहेली में फंस गई है, जिसका हल निकालने पर ही उसे फाइनल में पहुंचने का मौका मिल सकता है। चलिए आपको बताते हैं वो पूरा गणित, जिससे टीम इंडिया के लिए अब भी फाइनल में पहुंचने की राह निकल सकती है।

टॉप-4 टीमों के दोगुने से ज्यादा मैच खेल चुका भारत

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा लेग में टीम इंडिया 8 टेस्ट मैच अब तक खेल चुकी है। फिलहाल कोलकाता टेस्ट मैच में हार के बाद डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में भारत चौथे नंबर पर है। यदि टेबल को देखा जाए तो भारत के मुकाबले बाकी तीनों टीमों ने उसके आधे से भी कम टेस्ट खेले हैं। नंबर-1 पायदान पर बैठे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने 3-3 टेस्ट खेले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर मौजूद श्रीलंका ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं। भारत ज्यादा मैच खेलने के कारण अंकों में बाकी चारों टीम से आगे है, लेकिन विनिंग परसेंटाइल की बात करें तो बाकी तीनों देश उससे बहुत आगे हैं। इसके चलते भारत के लिए मुश्किल बढ़ने जा रही है।

क्या है अब आगे का समीकरण

टीम इंडिया के लिए आगे का समीकरण पूरी तरह स्पष्ट है। हिंदुस्तान टाइम्स के एनालिसिस के मुताबिक, टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा सीरीज के अलावा अभी तीन सीरीज और खेलनी हैं। इनमें उसे 10 टेस्ट मैच खेलने हैं। अच्छी बात ये है कि इनमें से साउथ अफ्रीका के खिलाफ बचे हुए एक टेस्ट मैच के अलावा 6 अन्य टेस्ट भारत को अपने घर में खेलने हैं। लेकिन इनमें से एक भी टेस्ट हारना भारत के लिए उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर सकता है। ऐसे में अब टीम इंडिया को अपनी घरेलू पिचों पर सारे टेस्ट मैच जीतने होंगे और विदेशी धरती पर खेले जाने वाले चारों टेस्ट मैच में बराबरी करनी होगी। इस लिहाज से हर टेस्ट मैच का हर लम्हा टीम इंडिया के लिए अहम होगा।

ये हैं डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले

भारत का शेड्यूल

1 टेस्ट मैच गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है
2 टेस्ट मैच श्रीलंका जाकर उसकी पिचों पर खेलने हैं
2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के दौरे पर जाकर खेलने हैं
5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में खेलने हैं

ऐसे बंटते हैं एक डब्ल्यूटीसी चक्र में पॉइंट्स

18 टेस्ट मैच भारत को एक डब्ल्यूटीसी फाइनल से दूसरे फाइनल के बीच खेलने होते हैं।
216 पॉइंट्स इन 18 टेस्ट मैच में दोनों टीमों के लिए दांव पर लगे होते हैं।10 टेस्ट मैच अब इनमें से बचे हुए हैं, जिनसे 120 पॉइंट्स टीम इंडिया ले सकती है।
00 ड्रॉ का रिजल्ट यदि इन 10 टेस्ट मैच में रहा तो भारत का फाइनल खेलना केवल जीत पर निर्भर है

पीएम ने भारत के एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को बधाई दी...

नई दिल्ली,17 नवम्बर 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 2025 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को टूर्नामेंट में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए बधाई दी, जहाँ उन्होंने 10 पदक जीते, जो उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय तीरंदाजों ने छह स्वर्ण पदक जीते, जिनमें पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में एक ऐतिहासिक पदक भी शामिल है। हमारी तीरंदाजी टीम को एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में उनके अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई। उन्होंने 6 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते हैं। इनमें से उल्लेखनीय 18 साल बाद पुरुषों का रिकर्व स्वर्ण पदक है।

शिक्षा ही विकास का मूलमंत्र है,शिक्षा के बिना जीवन अधूरा : सीएम साय

रायपुर,17 नवम्बर 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जगदलपुर में शासकीय जगतु माहरा बस्तर हाईस्कूल के शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम में आज शामिल हुए। बस्तर हाईस्कूल के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने विद्यालय परिवार को शताब्दी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही विकास का मूलमंत्र है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा का अत्यधिक महत्व रहा है। नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में विदेशों से विद्वान ज्ञानार्जन के लिए आते थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में बस्तर हाईस्कूल तथा कांकेर के नरहरदेव विद्यालय जैसे संस्थान शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1926 में जब इस विद्यालय का निर्माण हुआ होगा,तब संसाधनों का अत्यधिक अभाव रहा होगा, लेकिन पिछले सौ वर्षों की विकास यात्रा में इस विद्यालय ने अनगिनत होनहार छात्र-छात्राओं को तैयार किया है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। आज उनमें से अनेक पूर्व छात्र इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने संस्था के निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएँ व्यक्त कीं। मुख्यमंत्री साय ने राज्य गठन के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने जगतु माहरा बस्तर हाईस्कूल के जीर्णोद्धार हेतु डेढ़ करोड़ रुपए तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास भवन निर्माण की घोषणा की। साथ ही विद्यालय की अन्य सभी आवश्यकताओं को प्राथमिकता से पूरा करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री साय ने इस कार्यक्रम में शैलेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा विद्यालय को प्रदान किए गए दो ड्रोन टोकन स्वरूप प्रदान किए,साथ ही शैलेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा विद्यालय को 50 ड्रोन उपलब्ध कराने की सहमति भी दी गई, जिससे तकनीकी शिक्षा को और प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने जगतु माहरा शासकीय बहुउद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जगदलपुर में शताब्दी समारोह पट्टिका का अनावरण किया। उन्होंने स्वर्गीय ठाकुर देवेन्द्र सिंह और स्वर्गीय श्रीमती शारदा ठाकुर की स्मृति में निर्मित दो स्मार्ट क्लासों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' अंतर्गत परिजात प्रजाति के पौधे का रोपण किया। शताब्दी समारोह के ध्वजारोहण के साथ विद्या-दायिनी मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की स्मारिका का भी विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी के पिता की स्मृति में आयोजित न्योता भोज कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों को भोजन परोसा। इसके अलावा जगतु माहरा बस्तर हाईस्कूल के वे सात पूर्व छात्र, जो पुलिस और सुरक्षा बल में सेवा के दौरान शहीद हुए, उनके छायाचित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने विद्यालय के शताब्दी समारोह के लिए बधाई देते हुए कहा कि आजादी से पहले 1926 में आरंभ हुए इस ऐतिहासिक विद्यालय के लिए यह दिन अत्यंत गौरवशाली है। पूर्व शिक्षक-शिक्षिकाओं तथा पूर्व छात्रों के लिए यह यादगार लम्हा है।

उन्होंने कहा कि इस संस्था से शिक्षा पाकर अनेक छात्र-छात्राएँ विभिन्न सेवाओं के माध्यम से समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वरिष्ठजनों से सीखने का आग्रह किया और विद्यालय की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का भरोसा दिलाया। विद्यालय के पूर्व छात्र और विधायक जगदलपुर किरण देव ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अविभाजित बस्तर जिले में बस्तर हाईस्कूल और कांकेर का नरहरदेव हाईस्कूल ही प्रमुख शिक्षा संस्थान थे,जहाँ समूचे अंचल के विद्यार्थी अध्ययन करते थे।

शराब घोटाले की जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर ईडी पर जताई नाराजगी

रायपुर,17 नवम्बर 2025। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि ऐसी कौन-सी जांच बची है जो अभी तक पूरी नहीं की जा सकी। कोर्ट ने कहा, एक तरफ कहते हो कि शराब घोटाले के आरोपियों को बेल नहीं देनी है, दूसरी तरफ कहते हो कि हम जांच कर रहे हैं। तो ऐसी कौन-सी जांच है जो अभी तक चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि जांच अधिकारी अपना पर्सनल एफिडेविड दाखिल करें, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ अभी कौन-सी जांच चल रही है। इस जांच को पूरा करने के लिए कितने समय की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है। बता दें कि ईडी ने लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही शराब घोटाले के केस में ईओडब्ल्यू ने भी केस दर्ज किया है, जिसकी जांच के बाद चार्जशीट पेश किया गया है। इस मामले में भी ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। वहीं,सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों को पहले दी गई अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा को स्थायी कर दिया। कोर्ट ने यह आदेश उन मामलों की सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की पीठ ने यह फैसला सीनियर एडवोकेट एस. नागमुथु और सिद्धार्थ अग्रवाल (याचिकाकर्ताओं की ओर से) और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी और एएसजी एस.डी. संजय (राज्य और ईडी की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद सुनाया। ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा सिंडिकेट के अहम हिस्सा थे। लखमा के निर्देश पर ही सिंडिकेट काम करता था। इनसे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी। वहीं,शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,जिससे छत्तीसगढ़ में एफएल-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। ईडी का दावा है कि लखमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की सुरक्षा स्थायी की

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों को पहले दी गई अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा को स्थायी कर दिया। कोर्ट ने यह आदेश उन मामलों की सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की पीठ ने यह फैसला सीनियर एडवोकेट एस. नागमुथु और सिद्धार्थ अग्रवाल (याचिकाकर्ताओं की ओर से) और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी और एएसजी एस.डी. संजय (राज्य और ईडी की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद सुनाया।

फर्जी महिला एसआई गिरफ्तार,कमल विहार के फ्लैट में लूटपाट मामले में खुलासा

रायपुर,17 नवम्बर 2025। फर्जी महिला एसआई अपने गुर्गो के साथ गिरफ्तार हो गई है, कमल विहार के फ्लैट में लूटपाट मामले में खुलासा पुलिस ने किया, जानकारी के मुताबिक मोनिका सचदेवा समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस हिस्ट्रीशीटर ने घर में की मारपीट और 25 हजार रुपए लूटकर फरार हो गए थे। मोनिका का भाई और एक साथी करण साहू फरार है। मुजगहन पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों का नाम पूजा सचदेव, निखील सचदेवश्च व 4 अन्य बताया। आरोपियों ने महंगी लैपटॉप, कैश सहित डेढ़ लाख के सामान लूट ले गए। वारदात को कृष्णा हाईट्स कमल विहार में होना बताया जा रहा है।इस खबर पर लगातार अपडेट जारी है।

कस्टडी से आरोपी फरार मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड

जांजगीर,17 नवम्बर 2025। अभिरक्षा से रेप के आरोपी के फरार होने के मामले में तीन आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। तीनों आरक्षकों को। लापरवाही बरतने के चलते एसपी विजय पांडे ने निलंबित किया है। तीनों निलंबित आरक्षकों को रक्षित केंद्र में अटैच किया गया है। थाना अकलतरा के अपराध क्रमांक 564/2023 धारा 376,511,323,506 354(क)(ख) भादवि एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अकलतरा के प्रकरण क्रमांक 44/24 के स्थायी वारंटी महावीर कंवर पिता बलराम कंवर उम्र 40 वर्ष निवासी कटनई को एवं दो अन्य वारंटियों को थाना अकलतरा के शासकीय वाहन से न्यायालय अकलतरा पेश करने हेतु आरक्षक क्रमांक 309 राजेंद्र कहरा, आरक्षक क्रमांक 425,उमेश यादव और आरक्षक क्रमांक 973 कमल बहादुर क्षत्रिय को अभिरक्षा में कल 16 नवंबर को रवाना किया गया था। उनकी अभिरक्षा से स्थाई वारंटी को फरार महावीर कंवर फरार हो गया। महावीर कंवर की सुरक्षा के प्रति सजग न रहकर वारंटी को फरार होने का अवसर प्रदान कर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाहीपूर्वक कृत्य करने के फलस्वरूप तीनों आरक्षकों को निलंबित कर रक्षित केंद्र संबद्ध कर दिया गया है।

भिलाई गोलीकांड...झारखंड से बुलाए थे 3 शूटर लेकिन निशाना चूका, 6 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग-भिलाई,17 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई गोलीकांड केस में पुलिस ने मास्टरमाइंड करण साव समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करण साव ने विकास प्रजापति की सुपारी झारखंड के 3 शूटर्स को दी थी। करण के कहने पर शूटर ने फायरिंग की, लेकिन विकास को नहीं लगी। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, शूटर्स ने साजिश के तहत विकास को डेकोरेशन के लिए ऑर्डर देने के बहाने से बुलाया था। इसके बाद 3 नकाबपोश शूटर्स ने फायरिंग की थी। वहीं फायरिंग स्पॉट पर खाली खोखे मिले थे, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल जामुल पुलिस झारखंड के शूटर्स की तलाश में जुटी है। दरअसल, 22 जनवरी 2024 को गाड़ी टकराने के विवाद में 12वीं के छात्र शिवम साव (17) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। शिवम साव करण साव का चचेरा भाई था। इस हत्या के मामले में विकास प्रजापति का चचेरा भाई राहुल प्रजापति अभी जेल में बंद है। शिवम की हत्या के बाद से करण साव गुस्से में था। खून का बदला खून से लेना चाहता था। शिवम की मौत का बदला लेने के लिए झारखंड के शूटर्स हायर किए। शूटर्स ने साजिश के तहत विकास प्रजापति को फोन किया और अंधेरे इलाके में बुलाया। इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की। वहीं पीड़ित विकास प्रजापति के भाई गंगाधर प्रजापति ने बताया कि वह लोग जामुल के कैंप-2 में रहते हैं।

छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ का यूपी-एमपी ओडिशा का धान जब्त

पुलिस ने तड़के 4 किलोमीटर पीछा कर रुकवाई गाड़ी, हड़ताल से नहीं लौटने पर 13 कर्मचारी बर्खास्त

रायपुर,17 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। इसी दौरान, प्रशासन ने अवैध रूप से दूसरे राज्यों से लाए जा रहे धान पर कार्रवाई की। 1 नवंबर से 16 नवंबर तक अभियान चलाकर पूरे प्रदेश में कुल 19,320 क्विंटल धान जब्त किया गया, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। तस्करों ने यूपी, एमपी और ओडिशा से धान लाया था, जिसे टास्क फोर्स ने घेराबंदी कर पकड़ा। सबसे ज्यादा महासमुंद में 4,266 क्विंटल धान जब्त किया गया है। जबकि दूसरे नंबर पर बलरामपुर है। जहां से 4,139 क्विंटल धान जब्त किया गया है। 15 नवंबर की तड़के सुबह साढ़े 3 बजे, पुलिस टीम ने साढ़े 4 किलोमीटर तक पीछा कर अवैध धान की गाड़ी रोकी। जांच में दोनों वाहनों से लगभग 200 बोरी अवैध धान बरामद हुआ। ड्राइवरों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद दोनों गाड़ियों को जब्त कर थाने में सुपुर्द कर दिया गया। बता दें कि प्रदेश में अब तक 19,464 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं, बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी कार्य से इनकार करने वाले 13 हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, जबकि तीन अन्य के खिलाफ स्ढ्ढक्र दर्ज करने का प्रस्ताव हैं। वहीं बेमेतरा में 23 कर्मचारियों को सेवा से अलग कर दिया गया है। रायपुर में 4 कर्मचारियों पर एफआईआर हुई है।

चेकपोस्ट और टास्क फोर्स की तैनाती : 1 नवंबर से 16 नवंबर तक टास्क फोर्स ने अलग-अलग जिलों में कुल 19,320 क्विंटल अवैध धान जब्त किया। तस्कर इसे दूसरे राज्यों से लाकर यहां बेचने की फिराक में थे। मार्कफेड ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि सीमावर्ती जिलों में विशेष चेकपोस्ट लगाए गए। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स ने निगरानी बढ़ाई, और इंटीग्रेटेड कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर के माध्यम से सतत मॉनिटरिंग की गई। सरकार किसानों से धान 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीद रही है। अगर यह धान बिक जाता तो इसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए होती।

अवैध परिवहन पर सख्ती बरतने 16 चेकपोस्ट बनाए गए : धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए सभी जिलों में चेक पोस्ट बनाए गए हैं। ओडिशा और अन्य राज्यों से आने वाले धान को रोकने 16 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। यहां राजस्व, कृषि, वन और पुलिस की टीम ड्यूटी में तैनात हैं।

इसके साथ ही मार्कफेड में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी की जा रही है।

गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी गेट बना रणभूमि...मौत की जांच की मांग पर छात्र उग्र,पुलिस ने रोका तो बढ़ा तनाव

बिलासपुर,17 नवम्बर 2025। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में बिहार के छात्र अर्सलान अंसारी की बीते दिनों हुई संदिग्ध मौत ने पूरे कैंपस में असुरक्षा और अविश्वास का माहौल बना दिया है। छात्रों का कहना है कि मौत की परिस्थितियाँ स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए वे निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर सोमवार को यूनिवर्सिटी गेट पर बड़ा और तीखा विरोध प्रदर्शन हुआ। अर्सलान अंसारी बिहार का रहने वाला था और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। बीते दिनों वह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है, जिससे छात्रों में आक्रोश गहराता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि मामले में जांच बेहद धीमी है और प्रशासन जानकारी छुपा रहा है।

गेट पर उमड़ी भीड़, छात्र चढ़े गेट पर : सोमवार की दोपहर हालात तब बिगड़े जब प्रदर्शन तेज होने लगा। सैकड़ों छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट पर एकत्र होकर नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध के बीच कुछ छात्र गेट पर चढ़ गए और वहां से जोर-जोर से 'अर्सलान को न्याय दो ', 'जवाब दो-जवाब दो' के नारे लगाते रहे। नाराज छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। उन्हें आरोप है कि मौत को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। स्थिति नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस बल भेजा गया। पुलिस ने छात्रों को नीचे उतरने और शांत रहने की अपील की, लेकिन भीड़ लगातार नारे लगाती रही। तनाव उस समय बढ़ गया जब स्न्स्ढ्ढ कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। छात्रों ने पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया, वहीं पुलिस का कहना था कि वे सिर्फ स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने यूनिवर्सिटी गेट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इससे अंदर-बाहर आने-जाने वाले छात्र और कर्मचारी भी फंस गए।

एक घंटे तक रुक गया आवागमन : करीब एक घंटे तक यूनिवर्सिटी गेट पर अफरातफरी का माहौल बना रहा। कई छात्र सड़क किनारे बैठकर विरोध करते रहे, जबकि कुछ गेट के ऊपर से लगातार नारे लगाते रहे। इस दौरान पुलिस अतिरिक्त बल बुलाने की कोशिश में जुटी रही ताकि स्थिति हाथ से न निकले। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने छात्रों से बात की और अर्सलान की मौत की निष्पक्ष व तेज जांच का आश्वासन दिया। प्रशासन की ओर से भी जानकारी दी गई कि मामले में पुलिस मेडिकल और तकनीकी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव...अब ई-ट्रैक पर होगा टेस्ट

एआई कैमरों से होगी निगरानी...

रायपुर,17 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पुरानी प्रक्रिया अब इतिहास बनने वाली है। रायपुर के बीरगांव स्थित ड्राइविंग संस्थान को अत्याधुनिक तकनीक से अपग्रेड करने की शुरुआत हो गई है। स्थानीय लोगों में भी इस बदलाव को लेकर चर्चा तेज है। परिवहन विभाग ने ई-ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक यानी ई-ट्रैक निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह नया ट्रैक पूरी तरह स्मार्ट तकनीक से लैस होगा, जिसमें टेस्ट देने वाले हर दावेदार की गतिविधि एआई कैमरों और सेंसर तकनीक से स्वतः रिकॉर्ड होगी। नए ई-ट्रैक पर सड़क पर वाहन नियंत्रण, लेन अनुशासन,गति नियंत्रण और सिग्नल पालन जैसे सभी मानक सेंसर अपने आप कैप्चर करेंगे। रायपुर के साथ दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा,जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा में भी यही ई-ट्रैक विकसित किए जाएंगे। कुछ महीनों बाद छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी तरीके से लिया जाएगा। परिवहन विभाग का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी, क्योंकि अब टेस्ट में वही पास होगा जो वास्तव में प्रशिक्षित और योग्य होगा। एल-शेप, एच-शेप, ब्रेक टेस्ट, स्लोप जैसे सभी जरूरी परीक्षण अब सेंसर्स द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे।

चिकित्सा शिक्षा विभाग में 125 सहायक प्राध्यापक के पदों पर होगी सीधी भर्ती

रायपुर,17 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में 125 सहायक प्राध्यापक पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विषयों में बड़ी संख्या में पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, बालरोग, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी जैसे प्रमुख विभाग शामिल हैं। राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के 35 विभागों में 125 सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन 25-11-.2025 से 24-12-.2025 तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा उपलब्ध लिंक पर किए जा सकेंगे। इन 125 पदों में 45 अनारक्षित, 21अजा, 43 अजजा , 16 अपवि वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अवसर प्रदान किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में लम्बे समय से रिक्त पड़े पद भरेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश के भविष्य के डॉक्टरों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला...अब 15 साल पुरानी गाड़ियां होंगी स्क्रैप,नई गाड़ियों पर मिलेगी 25प्रतिशत की छूट...

रायपुर,17 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुराने वाहनों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब 15 साल से ज्यादा पुराने शासकीय और गैर-शासकीय वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। रायपुर में इस फैसले की चर्चा पूरे प्रशासनिक हलकों में तेज है। यह निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के निर्देशों के बाद लिया गया है। परिवहन विभाग ने सभी विभागों और विभागाध्यक्षों को तत्काल ऐसे वाहनों की सूची भेजने के आदेश दिए हैं। व्यय विभाग के अनुसार, जितने वाहन स्क्रैप होंगे उसी के आधार पर सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। परिवहन विभाग ने 2,000 शासकीय और 4,000 गैर-शासकीय गाड़ियों को स्क्रैप करने का लक्ष्य तय किया है। सरकार का उद्देश्य पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकना और वाहनों को अपडेट करना है। स्थानीय स्तर पर भी लोग इस फैसले को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि शहर की सड़कों पर कई पुरानी गाड़ियां आज भी दौड़ रही हैं। 21 नवंबर को महानदी भवन में परिवहन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। इसमें सभी विभागीय अधिकारियों को 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों का पंजीयन नंबर, वाहन आवंटित व्यक्ति या संस्था का नाम, वाहन का प्रकार, वाहन अभी संचालित है या नहीं और पहले कोई वाहन स्क्रैप किया गया है तो उसकी प्रक्रिया जैसी जानकारियां प्रस्तुत करनी होगी।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यदि कोई वाहन रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से स्क्रैप करवाता है, तो नई गाड़ी खरीदने पर उसे 25% टैक्स की छूट मिलेगी। इसके लिए एक ऑनलाइन 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट' जारी किया जाएगा, जिसे प्रदेश की सभी ऑटोमोबाइल डीलरशिप में मान्य माना जाएगा। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि इससे नई गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों की संख्या घटेगी।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह*(पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2023-2025-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)

CMYK